Machine Translated by Google

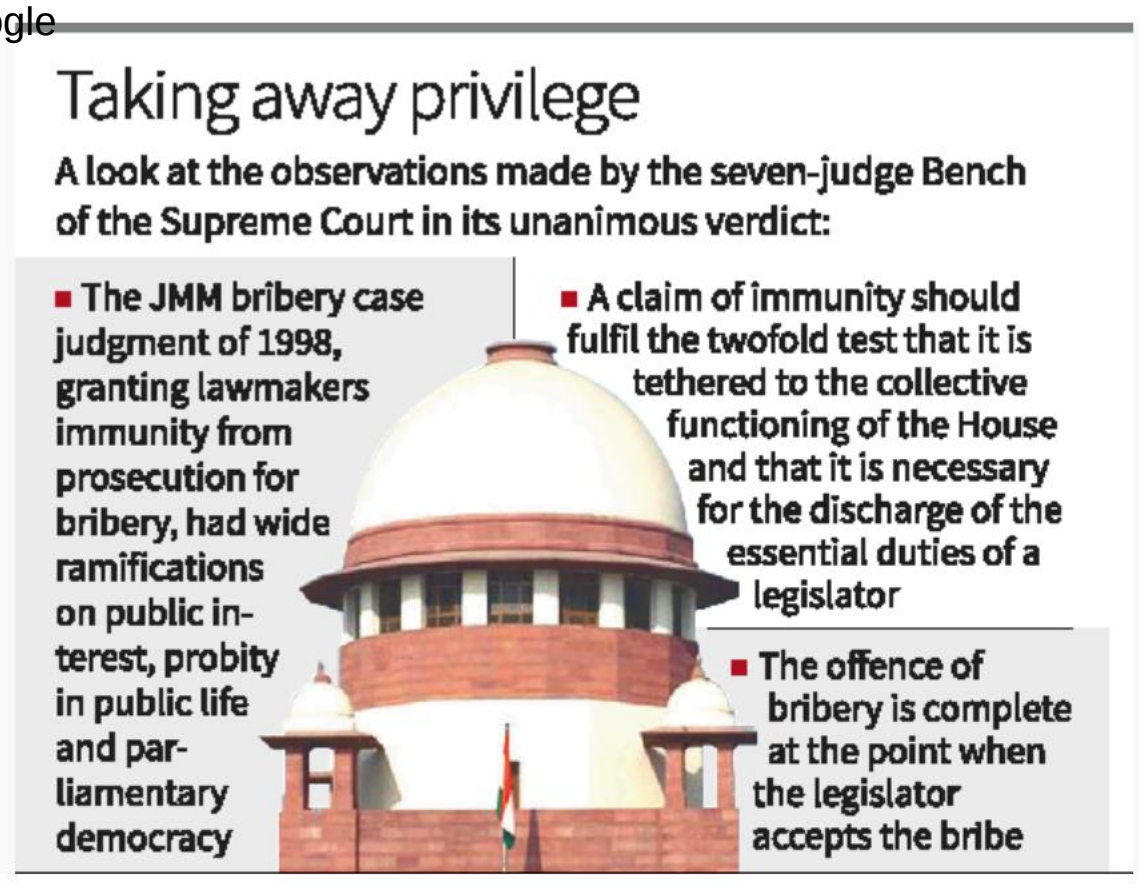

SC ने रिश्वत लेने वाले विधायकों की छूट खत्म की

Seven-judge Bench overrules the 25-year-old JMM bribery case judgment, saying representative democracy is at stake; the court dismisses the fears of abuse of law by political parties in power

KRISHNADAS RAJAGOPAL,
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की बेंच ने सोमवार को घोषणा की कि संसदीय विशेषाधिकार या छूट उन विधायकों को आपराधिक मुकदमे से नहीं बचाएगी जो संसद या राज्य विधानसभाओं में वोट देने या बोलने के लिए रिश्वत लेते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "विशेषाधिकार और छूट देश के सामान्य कानून से छूट का दावा करने के प्रवेश द्वार नहीं हैं... विधायिका के सदस्यों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है।"

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा लिखे गए सर्वसम्मत फैसले ने सुप्रीम कोर्ट के 25 साल पुराने बहुमत के दृष्टिकोण को खारिज कर दिया, जो 1998 के जेएमएम रिश्वत मामले के फैसले में दिया गया था, कि रिश्वत लेने वाले कानूनविदों को भ्रष्टाचार के मुकदमे से छूट दी गई थी। आगे बढ़ें और सहमति के अनुसार सदन में मतदान करें या बोलें।

सात जजों की बेंच ने कहा कि जेएमएम रिश्वत मामले में पांच जजों की बेंच में बहुमत में गलती हुई है। अदालत गंभीर त्रुटि को बरकरार नहीं रखना चाहती थी। प्रतिनिधि लोकतंत्र ख़तरे में था। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार का पैसा स्वीकार करते ही रिश्वतखोरी का अपराध पूरा हो गया।

“विधायक को आपराधिक मुकदमे का सामना करना पड़ेगा चाहे वह रिश्वत देने वाले के पक्ष में भाषण दे या वोट दे।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, रिश्वत का अपराध धन स्वीकार करने या धन स्वीकार करने का समझौता होने पर पूरा होता है।

संविधान पीठ ने उन धारणाओं को खारिज कर दिया कि संसदीय प्रतिरक्षा को कम करने से सदन में विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए वोट या भाषण को आपराधिक जांच का सामना करना पड़ेगा और इस प्रकार सत्ता में राजनीतिक दलों द्वारा कानून के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी।

CONTINUED ON ❯ PAGE 10

Machine Translated by Google

SC ने रिश्वत लेने वाले विधायकों की छूट खत्म की

अदालत ने कहा, रिश्वत लेने वाले कानून निर्माता "संविधान के आकांक्षात्मक और विचारशील आदर्शों के लिए विनाशकारी थे और एक ऐसी राजनीति बनाते हैं जो नागरिकों को एक जिम्मेदार, उत्तरदायी और प्रतिनिधि लोकतंत्र से वंचित करती है"।

मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने तर्क दिया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें सदन में मतदान शामिल है, और अनुच्छेद 105 और 194 के तहत विधायकों को दी गई परिचारक छूट रिश्वत देने या लेने तक विस्तारित नहीं है।

फैसले में कहा गया कि संसदीय प्रतिरक्षा तभी लागू होगी जब कोई विधायक "एक विचारशील, आलोचनात्मक और उत्तरदायी लोकतंत्र को बढ़ावा देने" के लिए कार्य करेगा।

Twofold test

उन्मुक्ति या संसदीय विशेषाधिकार की ढाल का दावा दो परिस्थितियों में किया जा सकता है। एक, यदि किसी विधायक के कार्यों का उद्देश्य एक सामूहिक निकाय के रूप में सदन और उसके सदस्यों की गरिमा और अधिकार को बढ़ाना था और, दूसरे, यदि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध और गिरफ्तारी से मुक्ति के अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे थे। अन्य। अदालत ने कहा कि अगर यह दो-तरफा परीक्षण में विफल रहता है तो प्रतिरक्षा का दावा टिक नहीं पाएगा।

“एक व्याख्या जो एक सांसद को रिश्वतखोरी के अपराध के लिए अभियोजन से छूट का दावा करने में सक्षम बनाती है, उन्हें कानून से ऊपर रखेगी। यह संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ कामकाज के प्रतिकूल और कानून के शासन के लिए विध्वंसक होगा, ”मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा।

रिश्वतखोरी के आरोपों पर आपराधिक अदालतों और विधायिका के सदनों का समानांतर क्षेत्राधिकार है।
कोई भी दूसरे के अधिकार क्षेत्र को नकार नहीं सकता। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा, "एक आपराधिक अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए एक सक्षम अदालत द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार और विधायिका के एक सदस्य द्वारा रिश्वत स्वीकार करने के संबंध में अनुशासन के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने का सदन का अधिकार अलग-अलग क्षेत्रों में मौजूद है।" निर्धारित।

यह संदर्भ झामुमो नेता सीता सोरेन द्वारा दायर एक अपील में आया है, जिन पर 2012 के राज्यसभा चुनावों में एक विशेष उम्मीदवार के लिए वोट करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस आधार पर दोषी होने से इनकार कर दिया कि उन्होंने आधिकारिक उम्मीदवार के लिए मतदान किया था। उनकी अपनी पार्टी, सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने आरोपपत्र को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने शीर्ष अदालत का रुख किया था।

Machine Translated by Google

सुप्रीम कोर्ट एफआईआर को क्लब करने की टीएन मंत्री की याचिका पर सुनवाई करेगा

KRISHNADAS RAJAGOPAL,
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट सोमवार को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन की 'सनातन धर्म' पर उनकी टिप्पणियों को लेकर कई राज्यों में उनके खिलाफ दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को क्लब करने की याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया।

शुरुआत में, जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि श्री स्टालिन कोई आम आदमी नहीं थे और उन्हें अपनी टिप्पणियों के बाद होने वाले परिणामों का एहसास होना चाहिए था।

'Right to a fair trial'

मंत्री ने जवाब दिया कि वह मामले की योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि प्रक्रिया के सवाल पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि कई एफआईआर दर्ज करना निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकार का उल्लंघन है और यह "अभियोजन से पहले उत्पीड़न" के समान है।

'You are not a layman'

"आप अनुच्छेद 19(1)(ए) [स्वतंत्र भाषण] का दुरुपयोग करते हैं, आप अनुच्छेद 25 [अंतरात्मा की स्वतंत्रता] का दुरुपयोग करते हैं। अब आप अनुच्छेद 32 [मौलिक अधिकारों की रिट संरक्षण] के तहत यहां आ रहे हैं... आप आम आदमी नहीं हैं।
आप मंत्री हैं. आपको परिणामों का एहसास होना चाहिए था,'' न्यायमूर्ति दत्ता ने तमिलनाडु के मंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी, मुकुल रोहतगी और पी. विल्सन को संबोधित किया।

न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि श्री स्टालिन इनमें से प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं।

Machine Translated by Google

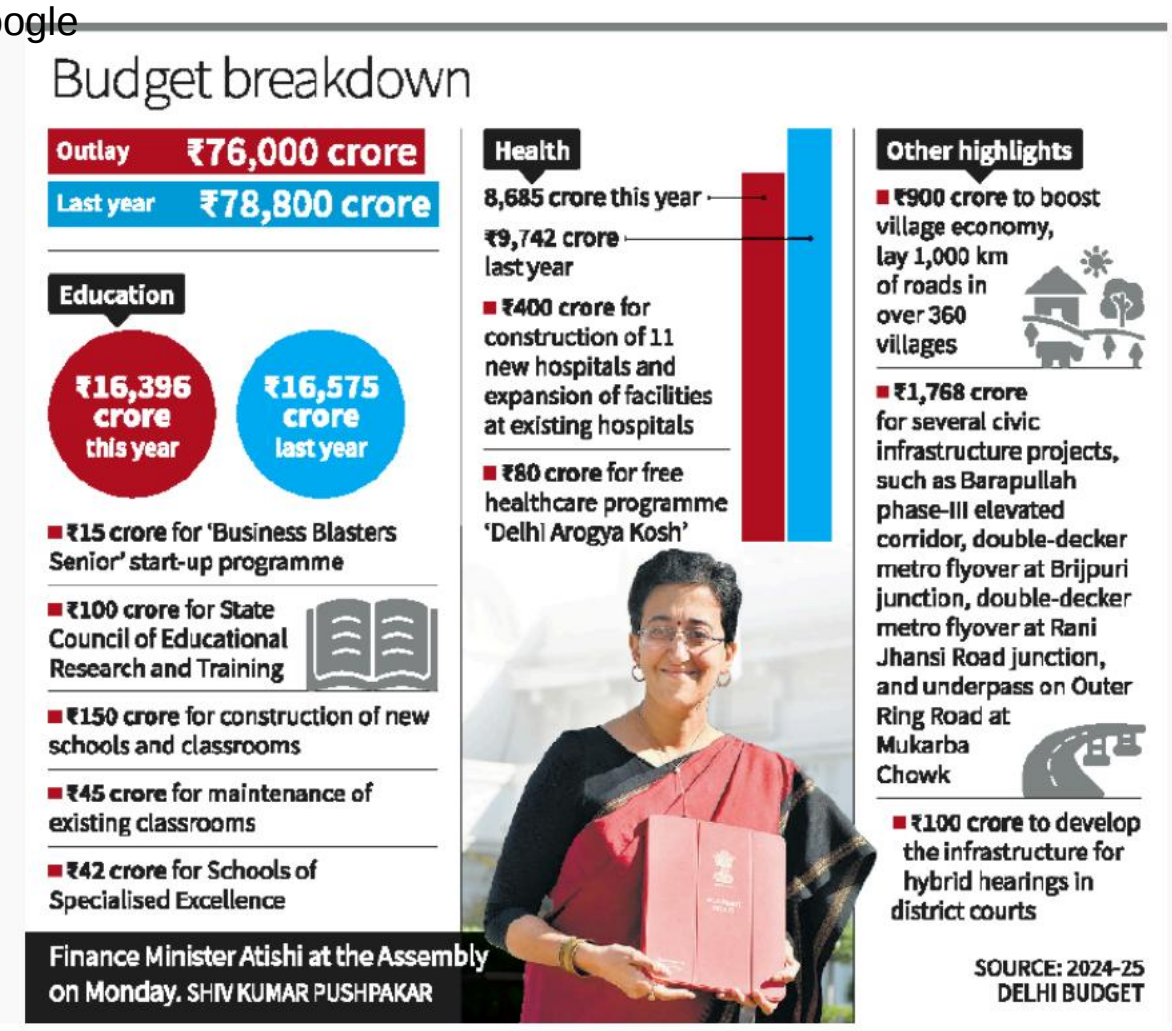

Finance Minister Atishi at the Assembly on Monday. SHIV KUMAR PUSHPAKAR

वित्त मंत्री का कहना है कि ₹76,000 करोड़ का बजट दिल्ली में 'राम राज्य' हासिल करने में मदद करेगा

Education continues to receive lion's share of the budget, which sees a drop of 3.7% compared to last year's outlay; Centre not giving Delhi its rightful share from central pool of taxes, says Atishi

THE HINDU BUREAU
नई दिल्ली

वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली के लिए 76,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया और कहा कि इसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी (आप) के "राम राज्य" के सपने को साकार करना।

अपने लगभग 100 मिनट के भाषण में, सुश्री आतिशी ने "राम राज्य" के 32 संदर्भ दिए और हिंदू से बड़े पैमाने पर उद्धरण दिए आप सरकार का लगातार 10वां बजट पेश करते हुए महाकाव्य।

"मैं समझता हूं कि स्थापित होने की इस यात्रा में हमें अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। हालाँकि, मैं यह बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ पिछले 10 वर्षों में दिल्ली के आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलाव आए हैं।''
आतिशी ने अपने पहले बजट भाषण में कहा.

"कहा जाता है कि वहाँ कोई गरीबी नहीं थी राज्य हर परिवार समृद्ध था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मानना है कि गरीबी मिटाने का एकमात्र तरीका हर बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करना है। इसलिए, हम हैं शिक्षा के लिए उच्चतम आवंटन प्रदान करना जारी रहेगा," उन्होंने कहा।

पिछले साल की तुलना में 2024-25 के कुल बजट में 3.7% की कटौती देखी गई। स्वास्थ्य के लिए आवंटन और शिक्षा क्षेत्रों में भी पूर्ण रूप से गिरावट देखी गई।

मंत्री ने 400 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं के लिए अपनी मुफ्त बिजली योजना जारी रखते हुए कहा दिल्ली सोलर पॉलिसी-2023, जो अभी गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में है, जो भी उपभोक्ता इससे अधिक का उपयोग करता है यदि वे पर्याप्त सौर पैनल स्थापित करते हैं तो 400 यूनिट बिजली पर शून्य बिल आएगा।

सुश्री आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सभी राज्य सरकारें प्राप्त करती हैं उन्होंने कहा कि करों और शुल्कों के केंद्रीय पूल से उनका हिस्सा, हालांकि, दिल्ली को कभी भी उसका उचित हिस्सा नहीं मिला है।

"जबकि अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए गए सभी करों का 41% प्राप्त होता है, दिल्ली को केंद्रीय पूल से हिस्सा मिलता है वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक केवल ₹325 करोड़ पर ही रुका रहा। 2023-24 में, यह शून्य हो गया, "उसने कहा। "अगर केंद्र सरकार दिल्ली को उसका उचित हिस्सा देती है, तो शहर को हर साल ₹7,200 करोड़ से अधिक मिलेगा, "सुश्री आतिशी ने कहा। उन्होंने कहा, अपना उचित हिस्सा नहीं दिए जाने के बावजूद, दिल्ली का बजट उल्लेखनीय रूप से ₹30,940 करोड़ से बढ़ गया। 2014-15 से इस वर्ष ₹76,000 करोड़।

Machine Translated by Google

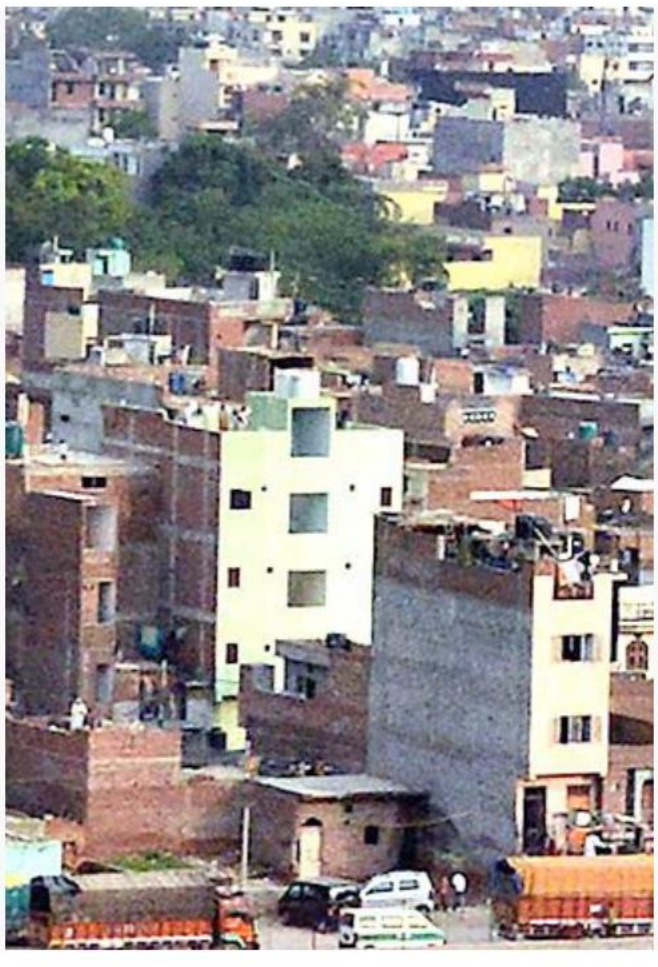

₹902 करोड़। अवैध कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए आवंटित

वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में कहा कि शहर की 30 फीसदी आबादी अवैध कॉलोनियों में रहती है. फाइल फोटो - Photo:

PRESS TRUST OF INDIA
नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए अपने बजट में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

वित्त मंत्री आतिशी ने अपने बजट भाषण में कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गियों में युद्ध स्तर पर पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है।

“दिल्ली में संभवतः कोई झुग्गी-झोपड़ी नहीं है जहां हर घर तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। आज, 99.6% अनधिकृत कॉलोनियों में पानी की पाइपलाइनें हैं, ”उसने कहा।

4,243 किलोमीटर लंबा सीवरेज नेटवर्क है जिससे अब 1,031 अनधिकृत कॉलोनियां जुड़ी हुई हैं। मंत्री ने कहा, 2014 के बाद, अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2,422 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइन और 3,100 किलोमीटर सीवर पाइपलाइन बिछाई ताकि हर दिल्लीवासी को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा, "भगवान राम के जीवन ने हमें सिखाया है कि हमें सबसे पहले उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं।"

दिल्ली की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अनधिकृत कॉलोनियों में रहता है. सुश्री आतिशी ने अपने भाषण में कहा, लगभग 1,800 ऐसी कॉलोनियाँ हैं, जो शहर की 30% आबादी को आश्रय देती हैं।

मंत्री ने दावा किया, एक समय था जब अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के प्रति सरकारों का रवैया "अत्यधिक उदासीन था और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था"।

“उस दौरान सरकारें उन्हें केवल वोट मांगते समय ही याद करती थीं। इन कॉलोनियों में पीने का पानी नहीं था, सड़कें, सीवरेज या नालियां नहीं थीं. ये कॉलोनियाँ गंदगी और कूड़े से घिरी हुई थीं, ”उसने आरोप लगाया।

‘Focus on quality life’

दिल्ली के वित्त मंत्री ने कहा कि इन कॉलोनियों के अधिकांश निवासी प्रवासी थे जो बेहतर जीवन के सपने लेकर दिल्ली आए थे लेकिन वे ''घटिया परिस्थितियों में रहने को मजबूर थे।'' वित्त मंत्री ने कहा, ''उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की भी कमी थी।''

उन्होंने कहा, ''हमने अनधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे का विकास करना और लोगों को सम्मानजनक जीवन देना अपनी प्राथमिकता बनाई है।'' उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने ऐसी 1,355 कॉलोनियों में 5,175 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई हैं।

Machine Translated by Google

Sandeshkhali, the untold story

द्वैपायन भट्टाचार्य

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के राजनीतिक अध्ययन केंद्र में प्रोफेसर हैं।

नई दिल्ली

संदेशखाली फ्रेंचाइजी राजनीति का एक उपयुक्त उदाहरण है, जिसे दो सम्मोहक और शक्तिशाली आख्यानों के माध्यम से बताया गया है

पश्चिम बंगाल में संदेशखाली के लिए दो रास्ते हैं। एक आपको हिंदू-मुस्लिम विभाजन के बीच ले जाता है। दूसरा अधिग्रहण-वंचन विभाजन के माध्यम से। दोनों कहानियाँ सम्मोहक और सशक्त हैं।

पहली कहानी में खलनायक का नाम है तृणमूल नेता शेख शाहजहां और पीड़ित हैं हिंदू महिलाएं.
यह कहानी असहाय हिंदू पर मुस्लिम हमलों की लंबी कहानी में फिट बैठती है, जब भी और जहां भी हिंदू कमजोर या अल्पसंख्यक होता है, चाहे वह बांग्लादेश, पाकिस्तान या संदेशखाली जैसी जगहें हों। इस कहानी की ताकत उस व्यापक आख्यान को पुष्ट करती है जिसने हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल में विभाजन के घाव को बहाल करते हुए लोकप्रियता हासिल की है।

समस्या यह है कि सन्देशखाली में कहानी न केवल आंशिक है बल्कि झूठी भी है। यहां महिलाओं के खिलाफ कथित अपराधों के तत्काल अपराधी उत्तम सरदार और शिबाप्रसाद हाजरा हैं, जो दोनों गैर-मुस्लिम हैं। तीसरा अजीत मैती है, जिस पर पिछले सप्ताह संदेशखाली के ग्रामीणों ने हमला किया था.

जनता के दबाव में, ममता बनर्जी की पुलिस ने तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि शेख फरार था। उन्हें इतने लंबे समय तक बचाए रखने से आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए सुश्री बनर्जी के मुस्लिम 'तुष्टिकरण' के आरोप को हवा देने में मदद मिली। दोनों संदेशखाली ब्लॉकों में हिंदू लगभग 'अल्पसंख्यक' हैं: एक में 70% और दूसरे में 77%, ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं।

A crisis of governance

हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के बजाय, संदेशखाली स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी के शासन मॉडल के संकट को दर्शाता है। कई अन्य राज्यों के विपरीत, जहां लोग जाति, आदिवासी, भाषाई या धार्मिक पहचान के आधार पर समूह बनाते हैं, पश्चिम बंगाल में विभाजन के बाद जीवन और आजीविका के लिए संघर्ष हुआ, लोग सुरक्षा और प्रावधानों दोनों के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े रहे।

वाम मोर्चे के लंबे शासन के दौरान, आधिपत्यवादी सीपीआई (एम) की अच्छी तरह से समन्वित संरचना के कारण, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के लिए मास्टर कुंजी की पेशकश करने में व्यक्तियों और समूहों की पक्षपातपूर्ण संबद्धताएं और अधिक मजबूत हो गईं। पार्टी संबद्धता ने लोगों को एक पहचान दी, जिसने बदले में, पार्टी-सोसाइटी नामक एक संलयन बनाया। वाम मोर्चे के अंतिम वर्षों में, शिक्षित मध्यम वर्ग के पार्टी नेताओं को धीरे-धीरे लेकिन लगातार जमीनी स्तर पर उद्यमशील व्यक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा था जो या तो अपेक्षाकृत संपन्न किसानों का प्रतिनिधित्व करते थे या छोटे व्यापार और व्यवसाय चलाने वाले थे।

वाम मोर्चे की हार के साथ, इन स्थानीय राजनीतिक प्रबंधकों में से सबसे महत्वाकांक्षी ने पाला बदल लिया और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में शामिल हो गए।

सुश्री बनर्जी को पहले ही एहसास हो गया था कि हालाँकि उन्हें पार्टी समाज के साथ काम करना है, लेकिन वह सीपीआई (एम) की तरह सरकार नहीं चला सकतीं। अपनी पार्टी में, बिना किसी स्थिर आदेश के पदानुक्रम के उन्होंने अकेले ही सार्वभौमिक प्राधिकार प्राप्त किया। उसने इसकी भरपाई त्रिस्तरीय तरीके से की। उन्होंने कुछ प्रमुख नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों को, चाहे उनकी रैंकिंग कुछ भी हो, अपनी सीधी कमान के तहत लाया और पार्टी कार्यकर्ताओं के मुकाबले उन पर अपना विश्वास जताया। उन्होंने जातीय, जातीय और धार्मिक समुदाय के नेताओं से दोस्ती की और उन्हें पार्टी में शामिल किया। इसके अलावा, उन्होंने स्थानीय पार्टी सरदारों को पूरी व्यक्तिगत वफादारी के बदले उनके संदिग्ध व्यवसायों का विस्तार करने के लिए सुरक्षा प्रदान की। ये उद्यमशील राजनीतिक प्रबंधक अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग करने के लिए तत्पर थे - स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ मिलीभगत करके - भूमि, जंगल, रेत, कोयला, मछली पालन, खाद्यान्न से जुड़े कानूनी और अवैध व्यवसायों से जितना संभव हो उतना लाभ हड़पने और नकदी निकालने के लिए। विभिन्न सरकारी योजनाएँ और अनुबंध। इनमें से अधिकांश लोग अपेक्षाकृत समृद्ध किसान परिवारों से हैं, जिन्होंने पहले वाम मोर्चे के भूमि सुधारों के कारण अपनी जमीन खो दी थी, लेकिन अंततः सत्ता के स्थानों पर तैनात हुए - पहले सीपीआई (एम) में और उसके बाद टीएमसी में।

पश्चिम बंगाल की लगातार औद्योगिक गिरावट के साथ, ये उद्यमशील व्यक्ति अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में मुख्य नियोक्ता हैं। सत्ता और लाभ के इस तरह के संयोजन ने पश्चिम बंगाल के विशाल ग्रामीण और अर्ध-शहरी बस्तियों में छोटी पूंजी का भाईचारा पैदा कर दिया है। ये सूक्ष्म विनियोगकर्ता और राजनीतिक नेता भी सुश्री को भुनाते हैं।

निजी जागीर चलाने के लिए बनर्जी की लोकप्रियता। वे अपनी स्थानीय शक्ति और समृद्धि के लिए सभी संभावित चुनौतियों को खत्म करते हैं, नियमित रूप से विपक्षी दलों को पंचायत चुनावों में अपने उम्मीदवारों को वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं।

टीएमसी अपने प्रमुख खिलाड़ियों को नियंत्रण और आदेश के 'पट्टे पर दिए गए' क्षेत्रों में ताकत और धन के ऐसे दोतरफा प्रवाह का प्रतीक है। ध्यान दें, संरचना मुख्य रूप से पूर्ण भौतिक लाभ पर खड़ी है और दीदी के 'अच्छे इरादों' में लोगों के अस्पष्ट विश्वास को अपने नैतिक आधार के रूप में उपयोग करती है। एक लंबे निबंध में, मैंने इसे 'फ्रैंचाइज़ी राजनीति' कहा है ("सहयोग और संघर्ष का: ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल में 'फ्रैंचाइज़ी राजनीति' का निर्माण", 9 सितंबर, 2023)।

आर्थिक & राजनीतिक साप्ताहिक (ईपीडब्ल्यू),

The essence of Sandeshkhali

सन्देशखाली फ्रेंचाइजी राजनीति का एक उपयुक्त उदाहरण है। यह संकट तब शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी शेख शाहजहां के घर गए। उन पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया. पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया. स्थानीय लोगों के लिए, शेख उनकी आजीविका का संरक्षक-प्रदाता है। शेख का नाम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) घोटाले की जांच के दौरान सामने आया था, जिसमें कथित तौर पर बड़ी मात्रा में खाद्यान्न को खुले बाजार में भेज दिया गया था।

अक्टूबर में, ईडी ने सुश्री बनर्जी की सरकार में पूर्व खाद्य और आपूर्ति मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक को गिरफ्तार किया था।
शेख ने उन्हें सूचना दी. जब मल्लिक ने उत्तर 24 परगना जिले पर अपनी जागीर चलायी, तो उन्होंने संदेशखाली के दो ब्लॉकों को अपने डिप्टी शेख को सौंप दिया, जिन्होंने बदले में संदेशखाली ब्लॉक-2 को शिबू हाजरा को सौंप दिया। उत्तम सरदार को हाजरा 'सब लेट' संदेशखाली ग्राम पंचायत। लाभ और शक्ति की एक स्पष्ट श्रृंखला खींची गई, जो टीएमसी की जीवनधारा है।

When the chain snapped

चेन क्यों टूट गई? यह टूट गया क्योंकि मल्लिक की गिरफ्तारी और शेख की घटनास्थल से अनुपस्थिति के कारण समीकरण बिगड़ गया। जैसे ही मीडिया ने संदेशखाली पर ध्यान केंद्रित किया, स्थानीय लोगों को अपना मुंह खोलने का साहस मिला। उन्होंने दो विशिष्ट आरोप लगाए: हाजरा और सरदार जैसे टीएमसी नेताओं ने अवैध रूप से उनकी कृषि भूमि को जब्त कर लिया और उन्हें बिना किसी मुआवजे के निजी मत्स्य पालन में बदल दिया। और टीएमसी कार्यकर्ता नियमित रूप से गांव की महिलाओं को देर रात पार्टी कार्यालय में बुलाते थे और उनका यौन शोषण करते थे। पहला भूमि सुधारों को उलटने का एक उत्कृष्ट मामला है जिसमें वाम मोर्चा ने 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में भूमिहीन और भूमि-गरीब किसानों के बीच निजी तौर पर रखी गई कृषि भूमि को एक निश्चित मात्रा से अधिक वितरित किया था। दूसरा किसी बाध्यकारी वैचारिक-नैतिक अनुशासन से रहित एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं द्वारा राक्षसी मर्दाना शक्ति का एक विशिष्ट प्रदर्शन है।

जैसा कि अनुमान है, टीएमसी अब खुद को शेख, हाजरा और सरदार से दूर करने का प्रयास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी इसे मुस्लिम गुंडों द्वारा हिंदू महिलाओं के शोषण के रूप में चित्रित करने में लगी हुई है। आज बंगाल में विपक्ष की जगह पर पार्टी के बड़े पैमाने पर कब्जे के साथ, इसे लोकसभा चुनाव से पहले के दिनों में ध्रुवीकरण के लिए उपजाऊ जमीन मिल सकती है। फिर भी, संदेशखाली की अनकही कहानी भूमि सुधारों को उलटने और तृणमूल कांग्रेस द्वारा लाड़-प्यार और प्रचारित ग्रामीण अमीरों के एक उभरते वर्ग द्वारा स्थानीय लोकतंत्र की अस्वीकृति में गरीबों की संपत्ति का दुरुपयोग करने की पूर्ण शक्ति को हड़पने में से एक है।

Machine Translated by Google

रूस-उत्तर कोरिया संबंधों में त्वरित परिवर्तन

2 में से 1 हर्ष वी. पंत

ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली में अध्ययन और विदेश नीति के उपाध्यक्ष और किंग्स में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं
कॉलेज लंदन

यह एक ऐसी साझेदारी है जो आम चुनौतियों और साझा रणनीतिक उद्देश्यों के बीच बनी है

सियोल के साथ दशकों पुराने एकीकरण लक्ष्य को छोड़ने सहित कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाइयों की एक श्रृंखला के बीच, प्योंगयांग तेजी से रूस के साथ अपने संबंधों को गहरा कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद से गति और गहराई में तेजी आई है, जिसके कारण मॉस्को के अधिकांश अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तनाव पैदा हो गया है। जुलाई 2023 में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के नेतृत्व में रूस के एक प्रतिनिधिमंडल की प्योंगयांग यात्रा के दौरान इसे और अधिक ईंधन मिला, जिसके तुरंत बाद सितंबर 2023 में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन की मास्को यात्रा हुई।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 2024 में एक बार फिर प्योंगयांग का दौरा करने की उम्मीद है, दोनों देश दोनों नेताओं के बीच एक शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं जहां "बहुत अच्छे" सौदों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। 2023 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को तेजी से आगे बढ़ाया गया है, उत्तर कोरिया में रूस के राजदूत, अलेक्जेंडर मत्सेगोरा का अनुमान है कि 2024 दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष होगा। पिछले महीने ही, श्री पुतिन ने उत्तर कोरियाई नेता को एक लक्जरी रूसी-निर्मित कार उपहार में दी थी, जिसका उपयोग श्री पुतिन स्वयं करते हैं।

Warming ties, greater collaboration

जबकि ऐतिहासिक रूप से, शीत युद्ध के युग के दौरान दोनों देशों ने राजनयिक संबंध बनाए रखे, जो मुख्य रूप से साम्यवादी राज्यों के रूप में साझा वैचारिक समानता से प्रेरित थे, मॉस्को और प्योंगयांग के बीच संबंधों में भू-राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव के कारण उतार-चढ़ाव का अनुभव हुआ। हाल के वर्षों में, रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंधों में उल्लेखनीय गर्माहट आई है, जो राजनयिक व्यस्तताओं और रणनीतिक सहयोग में प्रकट हुई है, प्योंगयांग यूक्रेन में चल रहे युद्ध के दौरान मास्को के लिए एक प्रमुख हथियार, युद्ध सामग्री, तोपखाने के गोले और एक अन्य पारंपरिक हथियार आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है। संकट।

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि दोनों देश संवेदनशील क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं जिनका खुलासा नहीं किया जा सकता है, साथ ही श्री पुतिन जासूसी उपग्रहों के विकास के लिए तकनीकी सहायता की भी पेशकश कर रहे हैं (एक उपलब्धि जो उत्तर कोरिया पिछले कुछ समय से लक्ष्य बना रहा है)। बीजिंग के साथ त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की भी चर्चा है, हालांकि ये अपुष्ट है। फरवरी 2024 में, प्योंगयांग ने भी COVID-19 महामारी के बाद रूस से पर्यटकों के पहले समूह का स्वागत किया।

रूस के लिए, एक ऐसे देश के रूप में जो विश्व राजनीति में जाति से बहिष्कृत है और फिर भी एक परमाणु शक्ति है, उत्तर कोरिया खेती के लिए एक उपयोगी पड़ोसी है। आर्थिक चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहे उत्तर कोरिया के लिए, रूस ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में विकास के लिए और यहां तक कि प्योंगयांग की पुरानी भोजन की कमी को दूर करने के लिए एक संभावित रक्षक के रूप में उभरा है। इससे पहले, रूस को उत्तर कोरिया के राजिन बंदरगाह से जोड़ने वाली राजिन-खासन रेलवे जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के ठोस प्रयासों को रेखांकित किया था।

The energy link

ऊर्जा सहयोग ने भी साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण पहलू बनाया है। रूस उत्तर कोरिया को ईंधन का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है और ऊर्जा क्षेत्र में और सहयोग तलाशने पर चर्चा चल रही है। हालाँकि, द्विपक्षीय सहयोग का मुख्य आधार हथियारों के बदले भोजन समझौता है, जिसके साक्ष्य अगस्त 2023 के दौरान सामने आए, हालाँकि दोनों देशों ने इस तरह के समझौते के अस्तित्व की पुष्टि नहीं की है। हालाँकि, इस तरह के समझौते की उपयोगिता निर्विवाद है, क्योंकि मास्को को यूक्रेन पर अपने आक्रमण को बनाए रखने के लिए हथियारों की आवश्यकता है, जबकि प्योंगयांग को वस्तुओं और भोजन की सख्त जरूरत है। अक्टूबर 2023 में सैटेलाइट छवियों ने उत्तर कोरिया-रूस सीमा के पास स्थित तुमांगंग रेल सुविधा पर माल ढुलाई रेल यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि को ट्रैक किया, जो उत्तर कोरिया द्वारा रूस को गोला-बारूद के हस्तांतरण की ओर इशारा करता है।

The American factor

इस मेल-मिलाप में योगदान देने वाले अन्य कारकों में संयुक्त राज्य अमेरिका और क्षेत्र में उसके सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत साझा चुनौती भी शामिल है। उत्तर कोरिया और रूस को पश्चिम के साथ अपने संबंधों में अलग-अलग स्तर के तनाव का सामना करना पड़ा है, जिससे उनकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में व्यावहारिक पुनर्मूल्यांकन हुआ है। मॉस्को उत्तर कोरिया के साथ जुड़ाव को पूर्वोत्तर एशिया में व्यापक सुरक्षा परिदृश्य को प्रभावित करने के एक साधन के रूप में देखता है।

रूस द्वारा अक्सर चीन के सहयोग से की गई कूटनीतिक पहल, पश्चिमी प्रभाव से स्वतंत्र रूप से क्षेत्रीय सुरक्षा वास्तुकला को आकार देने की इच्छा को रेखांकित करती है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री, चोए सोन-हुई ने अक्टूबर 2023 में देखा कि मॉस्को और प्योंगयांग के बीच शक्तिशाली संबंध संभावित रूप से वाशिंगटन, टोक्यो और सियोल के बीच एक मजबूत गठबंधन के अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रयासों को प्रभावित कर सकते हैं।

2023 में विकास, और 2024 में अब तक के संकेत, रूस और उत्तर कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 'मजबूती' की ओर इशारा करते हैं, दोनों देशों को एक-दूसरे में सहज सहयोगी मिल गए हैं। आम चुनौतियों और साझा रणनीतिक उद्देश्यों के बीच बनी इस साझेदारी का क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक भू-राजनीति पर दूरगामी प्रभाव है। जैसे-जैसे दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में अपने जुड़ाव और सहयोग को गहरा करेंगे, उनके संबंध कोरियाई प्रायद्वीप और व्यापक पूर्वोत्तर एशियाई क्षेत्र की गतिशीलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना है।

इस प्रकार, रूस-उत्तर कोरिया संबंध भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक उल्लेखनीय विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसका प्रभाव तत्काल द्विपक्षीय संबंधों से परे होता है।

Machine Translated by Google

गुनगुना व्यापार-बंद

World Trade Organization continues to struggle to foster free and fair trade

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था की नवीनतम बैठक एक दिन के विचार-विमर्श के बावजूद, वैश्विक व्यापार को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर बहुत कम प्रगति के साथ शुक्रवार देर रात संपन्न हुई। स्पष्ट रूप से, अबू धाबी में 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एमसी13) से किसी भी महत्वपूर्ण परिणाम की उम्मीदें शुरुआत में अधिक नहीं थीं। फिर भी, डब्ल्यूटीओ के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण था कि वह व्यापार के जिन नियमों को लागू करना चाहता है, उनके लिए बढ़ते तनावपूर्ण माहौल के बीच अपने जनादेश को पूरा करें। बीच की अवधि ने वैश्विक व्यापार वास्तुकला को महत्वपूर्ण झटके दिए हैं जैसे कि दुनिया के कुछ हिस्सों में संघर्षों के तीव्र प्रभाव, महत्वपूर्ण शिपमेंट मार्गों पर व्यवधान जो लंबे समय तक बने रहने की उम्मीद है, और एकल पर निर्भरता को कम करने के लिए आपूर्ति श्रृंखलाओं में पुन: अंशांकन। चीन जैसे आपूर्तिकर्ता। राष्ट्रों के बीच बढ़ती अंतर्मुखी प्रवृत्ति ने अलगाववादी, टैरिफ-भारी व्यापार नीतियों को भी उत्प्रेरित किया है जो सभी के लाभ के लिए खुले व्यापार के डब्ल्यूटीओ के प्राथमिक उद्देश्य से भटक जाती हैं। अबू धाबी घोषणापत्र में कुछ चुनौतियों का उल्लेख है, जैसे खुली, समावेशी और लचीली आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने की आवश्यकता, लेकिन दिखावटी दिखावे के अलावा इसमें बहुत कम सार है।

डब्ल्यूटीओ के 164 सदस्य-देशों के बीच जिनेवा (एमसी12) से आगे बढ़ाए गए अधिकांश मुद्दों पर मतभेद बने रहे, जिनमें भारत के लिए विशेष रुचि के क्षेत्र भी शामिल हैं, जैसे घरेलू खाद्य सुरक्षा या मत्स्य पालन क्षेत्र को सब्सिडी सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग के लिए कृषि में स्थायी समाधान। . डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक, न्गोजी ओकोन्जो-इवेला ने कहा है कि कृषि संबंधी विचार-विमर्श, पिछले दो दशकों से चल रहे कार्यों में, कुछ प्रगति हुई है क्योंकि आखिरकार काम करने के लिए एक पाठ है जिसके साथ निकाय भविष्य की बातचीत में इसे हासिल करने का प्रयास करेगा। . ई-कॉमर्स के लिए सीमा शुल्क से छूट, जिसे भारत ने देशों के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव का हवाला देते हुए समाप्त करने की मांग की थी, अब कम से कम दो और वर्षों तक जारी रहेगी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस नतीजे की बारीकी से व्याख्या करते हुए कहा है कि भारत "जरूरी नहीं" उनका पूरी तरह से विरोध करता हो।

चार साल से निष्क्रिय पड़ी डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान संस्था के पुनर्जीवन की संभावनाएं धूमिल बनी हुई हैं, हालांकि 2024 तक इस महत्वपूर्ण संस्था को पुनर्जीवित करने की जिनेवा प्रतिबद्धता दोहराई गई थी। MC13 में भारत की एक महत्वपूर्ण जीत दक्षिण अफ्रीका के साथ चीन के नेतृत्व में और 120 से अधिक देशों द्वारा समर्थित डब्ल्यूटीओ ढांचे में एक निवेश सुविधा समझौते को पेश करने के प्रयास को विफल करने के उसके सफल प्रयास थे। आगे बढ़ते हुए, भारत को संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर खेतों के लिए नीतिगत स्थान बनाए रखने के प्रयासों को दोगुना करना होगा। विश्व व्यापार संगठन को तेजी से ध्रुवीकृत होती दुनिया में प्रासंगिक बने रहने के लिए और भी बहुत कुछ करना होगा। सदस्यों को इसकी असफल द्विवार्षिक बैठकों को सफलता के रूप में प्रचारित करना सुविधाजनक लगता है, जो इसकी घटती प्रभावकारिता पर एक दुखद टिप्पणी है।

Machine Translated by Google

उपनाम में क्या है?

Women should not be tied to the name of their husbands

जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की तलाश में, पदानुक्रम, अन्यता और पितृसत्तात्मक मानसिकता को उचित ठहराने वाले हर कार्य को पूरी तरह से त्याग दिया जाना चाहिए। अपनी खुद की पहचान चुनने का अधिकार मांगते हुए, सुश्री दिव्या मोदी टोंग्या ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी कि तलाक के बाद उन्हें अपने पहले नाम पर वापस जाने की अनुमति दी जाए। वह एक सरकारी अधिसूचना के रूप में बाधा के बाद अदालत में पहुंची, जिसमें कहा गया था कि एक विवाहित महिला जो तलाक के बाद अपने मायके के नाम का उपयोग करना चाहती है, उसे या तो तलाक के कागजात या अपने पति से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख 28 मई तक केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। अपनी याचिका में, सुश्री मोदी टोंग्या ने कहा कि अधिसूचना "लिंग पक्षपातपूर्ण" है और उन महिलाओं के लिए अनावश्यक प्रतिबंध बनाती है जो अपना नाम चुनने के अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करना चाहती हैं - उनके मामले में उपनाम में बदलाव - अनुच्छेद 14, 19 का उल्लंघन करके और 21. एनओसी का विचार ही आपत्तिजनक है, चाहे तलाक की कार्यवाही हो या नहीं, और यह गहरी बैठी स्त्रीद्वेष को प्रतिबिंबित करता है जो किसी व्यक्ति की पसंद को नियंत्रित करना चाहता है। सुश्री मोदी टोंग्या को वह उपनाम चुनने में सक्षम होना चाहिए जिसके साथ वह सहज हों और इसके लिए संघर्ष न करना पड़े।

महिलाओं ने अक्सर उत्पीड़न की शिकायत तब की है जब उन्होंने कम प्रचलित रास्ता अपनाया है। उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं ने शादी के बाद अपने पति का उपनाम नहीं चुनने का फैसला किया है, उन्हें संयुक्त बैंक खाता खोलते समय, या स्कूल में बच्चे के प्रवेश के दौरान, या पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय अनावश्यक सवालों और कागजी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। . एक समाज जो पहले से ही जाति-आधारित पदानुक्रम से जूझ रहा है, उसे रिश्ते में किसी को ऊपरी हाथ देकर भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि लैंगिक पूर्वाग्रह, अंतर और अपमान के बिना सुरक्षित स्थान की दिशा में काम करना चाहिए। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में, राजनीतिक और सामाजिक रूप से, लैंगिक असमानताएं बरकरार हैं। महिलाएं घर पर अधिकांश अवैतनिक कार्य करती हैं, और अक्सर विभिन्न कारणों से उन्हें श्रम बल से बाहर कर दिया जाता है। एक लड़की या महिला क्या कर सकती है - और क्या नहीं - यह अक्सर परिवार के पुरुषों द्वारा तय किया जाता है; कभी-कभी महिलाएं भी परंपरा के नाम पर इस तरह के अपमान को स्वीकार कर लेती हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इस समय दुनिया में सबसे बड़ी मानवाधिकार चुनौती लैंगिक समानता हासिल करना और महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना है। विधायी समर्थन और मजबूत सामाजिक ढाँचे के साथ ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाए बिना महिलाओं के बराबर होने की बयानबाजी करना उद्देश्य को विफल कर देता है।

Machine Translated by Google

Campaign and conduct

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने राजनीतिक दलों को सलाह देते हुए नेताओं से कहा है कि वे 'जातियों को लुभाने, सांप्रदायिक भावनाओं और धार्मिक प्रतीकों को बढ़ावा देने, व्यक्तिगत मुद्दों को उठाने, महिलाओं को बदनाम करने और आधे-अधूरे सच को प्रचारित करने' के आधार पर मतदाताओं तक न पहुंचें। यह वास्तविक स्थिति से आँखें बंद करने का मामला है। राजनीति सहित सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में जाति, समुदाय और धर्म किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, यह सर्वविदित है। लोग चाहते हैं कि उनके प्रतिनिधि सार्वजनिक और निजी दोनों जगह अच्छे चरित्र वाले और ईमानदार हों। इनका पता केवल उम्मीदवारों और उनकी गतिविधियों के तरीके के बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक डोमेन में डालकर ही लगाया जा सकता है।

ईसीआई के निर्देश अक्सर मतदाताओं के अपनी (मतदाता की) पसंद के किसी भी आधार पर उम्मीदवार का चयन करने के इस नितांत व्यक्तिगत अधिकार का उल्लंघन करते प्रतीत होते हैं।

पीआरवी राजा,
पंडालम, केरल

ऐसा प्रतीत होता है कि ईसीआई वर्तमान प्रशासन के तहत अपनी निष्पक्षता और स्वतंत्रता खो रहा है। राजनीतिक परिदृश्य में धर्म के 'एकीकरण' में हालिया उछाल, विशेष रूप से राम मंदिर के उद्घाटन द्वारा बढ़ाया गया, बड़ी चिंता का विषय है। कुछ नेताओं द्वारा मंदिर यात्राओं में तेजी से वृद्धि और इस संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा प्रदान की गई व्यापक कवरेज केवल इस मुद्दे को बढ़ाती है।

राजनीति के साथ धर्म का अंतर्संबंध लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता और अखंडता के लिए संभावित खतरा पैदा करता है।

चुनावी अखंडता के संरक्षक के रूप में, ईसीआई को सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर बनाए रखने के उपाय लागू करने चाहिए।

एन नागराजन,
सिकंदराबाद

Political long jump

सत्ता में वापसी की इच्छा रखना किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन का अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 'सरकार के लिए 100 दिन के एजेंडे' पर चर्चा करके हद से आगे बढ़ गई है। मतदान के बाद' (पेज 1, 4 मार्च)। यह मनोरंजक और हास्यास्पद है और ऐसा प्रतीत होता है कि यह विपक्षी भारतीय गुट को किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक राजनीतिक दबाव के अधीन कर रहा है। भाजपा किस आधार पर इतनी आश्वस्त है? क्या यह ईवीएम का उपयोग करके कदाचार अपनाने जा रहा है या क्या हम चंडीगढ़ मेयर चुनाव जैसी स्थिति देखने जा रहे हैं? मतदाता मतदान केंद्र पर अपने मन और पसंद का प्रयोग करेंगे। पार्टी को इंतजार करना चाहिए.

A. Jainulabdeen,
Chennai

‘India’s parched IT capital’

बेंगलुरू, जिसे कभी पेंशनभोगियों के लिए स्वर्ग कहा जाता था और जो अपनी स्वास्थ्यप्रद जलवायु के लिए जाना जाता था, अब ऐसा नहीं है। शहर में बारिश होती है जो किसी भी तरह से मामूली नहीं है और हर बूंद को संरक्षित करने की जरूरत है। बेंगलुरु इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे इंसानों ने जीवन-निर्वाह वस्तु तक पहुंच को समाप्त कर दिया है। सरकार और सेना, जिनके पास शहर और उसके आसपास विशाल भूमि है, को बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन को अपनाना चाहिए। अकेले कावेरी पर निर्भर रहने से लगातार बढ़ते शहर की ज़रूरतें पूरी होने की संभावना नहीं है ('ग्राउंड ज़ीरो' पेज, 2 मार्च)।

H.N. Ramakrishna,
Bengaluru

बेंगलुरू अब उद्यानों का शहर नहीं रहा। महानगर खराब शहरीकरण का एक और उदाहरण है - चेन्नई की तरह - जहां जल निकाय खो गए हैं।

वीएम महेंद्रन, चेन्नई

LETTERS EMAILED TO LETTERS@THEHINDU.CO.IN

MUST CARRY THE FULL POSTAL ADDRESS AND THE FULL NAME OR THE NAME WITH INITIALS.

Machine Translated by Google

एक टीका जो छह कैंसरों को रोकता है

1 of 2 Hrishikesh Pai

FOGSI 2023 के अध्यक्ष हैं

गर्भाशय ग्रीवा और अन्य कैंसर की रोकथाम और शीघ्र पता लगाने के लिए एचपीवी टीकाकरण और कैंसर पूर्व घावों की जांच दो प्रमुख रणनीतियाँ हैं

जनवरी को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया गया। इसके अतिरिक्त, हर साल 4 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय एचपीवी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा में गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय के सबसे निचले हिस्से की सुरक्षा शामिल है। एचपीवी टीकाकरण से, हम सर्वाइकल कैंसर को रोक सकते हैं जो एक महिला के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। दुनिया भर में महिलाओं में चौथे सबसे आम कैंसर के रूप में, सर्वाइकल कैंसर हर साल 3,00,000 से अधिक महिलाओं की जान ले लेता है, या हर दो मिनट में एक जान ले लेता है। सर्वाइकल कैंसर से मरने वाली 10 में से नौ महिलाएं निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहती हैं। भारत में स्तन कैंसर के बाद सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर है। देश की जनसंख्या के आकार को देखते हुए, 15 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 500 मिलियन महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा है। यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के मामलों और मौतों की संख्या में काफी वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर के साथ, 2040 में भारत में सभी उम्र के लिए सर्वाइकल कैंसर के नए मामलों की कुल संख्या 1,91,347 होने का अनुमान है - 2020 में रिपोर्ट किए गए नए मामलों की संख्या में 54% की वृद्धि।

Strategies for prevention

1983 में जर्मन वैज्ञानिक हेराल्ड ज़्यूर हॉसेन ने प्रदर्शित किया कि मनुष्यों में सर्वाइकल कैंसर कुछ प्रकार के पेपिलोमा वायरस (मस्सा वायरस) के कारण होता है। एचपीवी महामारी विज्ञान और कैंसर के कारण में इसकी भूमिका के ज्ञान के परिणामस्वरूप रोकथाम और शीघ्र पता लगाने के लिए दो प्रमुख रणनीतियों का विकास हुआ है: एचपीवी टीकाकरण और कैंसर पूर्व घावों की जांच। यद्यपि सर्वाइकल कैंसर का उन्मूलन एक वास्तविक संभावना है, लेकिन त्रासदी यह है कि आज भी, कई कम संसाधन वाले समुदायों में सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिए प्रभावी हस्तक्षेप कार्यक्रमों का अभाव है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रणनीति उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल और न्यायसंगत स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ 2030 तक लागू होने वाले 90-70-90 ट्रिपल स्तंभ हस्तक्षेप की रूपरेखा तैयार करती है। हस्तक्षेप के लक्ष्य हैं: 90% लड़कियों को 15 वर्ष की आयु तक एचपीवी टीका पूरी तरह से लगाया जाना चाहिए; 70% महिलाओं को 35 वर्ष की आयु तक और फिर 45 वर्ष की आयु तक उच्च-प्रदर्शन स्क्रीनिंग परीक्षण का उपयोग करके जांच की जानी चाहिए; और सर्वाइकल प्री-कैंसर और कैंसर घावों से पीड़ित 90% महिलाओं को उपचार और देखभाल मिलनी चाहिए।

'एक्सेलरेटिंग ग्लोबल हेल्थ पाथवे: टू हेल्थ इक्विटी फॉर द जी20' शीर्षक वाली एक हालिया रिपोर्ट में विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए टीकों की समान पहुंच को बढ़ावा देने के लिए भारत की जी20 अध्यक्षता की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया है।
एचपीवी वैक्सीन को भारत में 2008 में पेश किया गया था। पर्याप्त देश-स्तरीय अध्ययन और सफल राज्य-स्तरीय रोल-आउट के बाद, इसे 2023 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश की गई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक प्रारंभिक घोषणा की गई थी। 2023 की शुरुआत में और, हाल ही में, वित्त मंत्री द्वारा अपने अंतरिम बजट भाषण में। वैक्सीन अब राष्ट्रीय लॉन्च का इंतजार कर रही है।

शोध से पता चलता है कि एचपीवी वैक्सीन पूरे भारत में सभी लड़कियों के लिए व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में, यह निजी बाजार में अपनी जेब से काफी अधिक कीमत पर उपलब्ध है। कई चिकित्सक सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी संक्रमण की घटनाओं और जोखिम को कम आंकते हैं। चिकित्सक भी एचपीवी टीकों की सुरक्षा और प्रभावशीलता को कम आंकते हैं। टीके की सुरक्षा और प्रभावशीलता में विश्वास की कमी के कारण योग्य किशोरों के माता-पिता को एचपीवी वैक्सीन की सिफारिश करने में झिझक होती है। चिकित्सक इस कैंसर रोकथाम टीकाकरण की अनुशंसा करने में भी संकोच कर सकते हैं क्योंकि एचपीवी संक्रमण मुख्य रूप से त्वचा से त्वचा के अंतरंग संपर्क के माध्यम से फैलता है। उन्हें यह भी महसूस हो सकता है कि एचपीवी वैक्सीन के बारे में मिथकों और गलत सूचनाओं के संबंध में माता-पिता के सवालों का जवाब देने में समय लग सकता है।

Facts and best practices

एचपीवी वैक्सीन के व्यापक रूप से प्रतीक्षित राष्ट्रीय रोल-आउट के समर्थन में, 80,000 से अधिक चिकित्सकों की संयुक्त सदस्यता के साथ फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज ऑफ इंडिया (FOGSI) और इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स (IAP) ने हाथ मिलाया है। सदस्य प्रसूति-स्त्री रोग विशेषज्ञों और बाल रोग विशेषज्ञों को एचपीवी टीकाकरण के तथ्यों के बारे में याद दिलाएं और इस कैंसर-रोकथाम टीके के बारे में माता-पिता के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करें। यह सुरक्षित और प्रभावी टीका छह एचपीवी कैंसर को रोकने में मदद कर सकता है। इनमें से पांच महिलाओं में होते हैं: वुल्वर, गुदा, योनि, गला और ग्रीवा। 9 वर्ष की आयु से सभी किशोरों को एचपीवी वैक्सीन की सिफारिश करना आईएपी टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने का हिस्सा है। हाल ही में, FOGSI गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस सिफ़ारिशों ने, सबूतों की समीक्षा के बाद, 9-14 वर्ष के प्राथमिक आयु समूह के लिए एचपीवी टीकाकरण के साथ-साथ 30 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला के लिए नियमित जांच की अपनी सिफारिश को मजबूत किया। जनसंख्या के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के ट्रैक रिकॉर्ड के साथ शीर्ष राष्ट्रीय चिकित्सा समितियों के रूप में, एफओजीएसआई और आईएपी यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हर लड़की एचपीवी टीकाकरण के माध्यम से गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से सुरक्षित रहे और हर महिला नियमित गर्भाशय ग्रीवा जांच के माध्यम से सुरक्षित रहे। ऐसा करते हुए, वे 2024 के मध्य तक अपने कैडर में कम से कम 20,000 एचपीवी चिकित्सक चैंपियन तैयार कर रहे हैं।

ये सदस्य चिकित्सक अपने साथियों और बड़े पैमाने पर समुदाय के बीच एचपीवी टीकाकरण के महत्व को साझा करेंगे।

चिकित्सक समाज में सबसे सम्मानित नेता हैं और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए विश्वसनीय स्रोत हैं। भारत में सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए उनके नेतृत्व की आवश्यकता है।

Machine Translated by Google

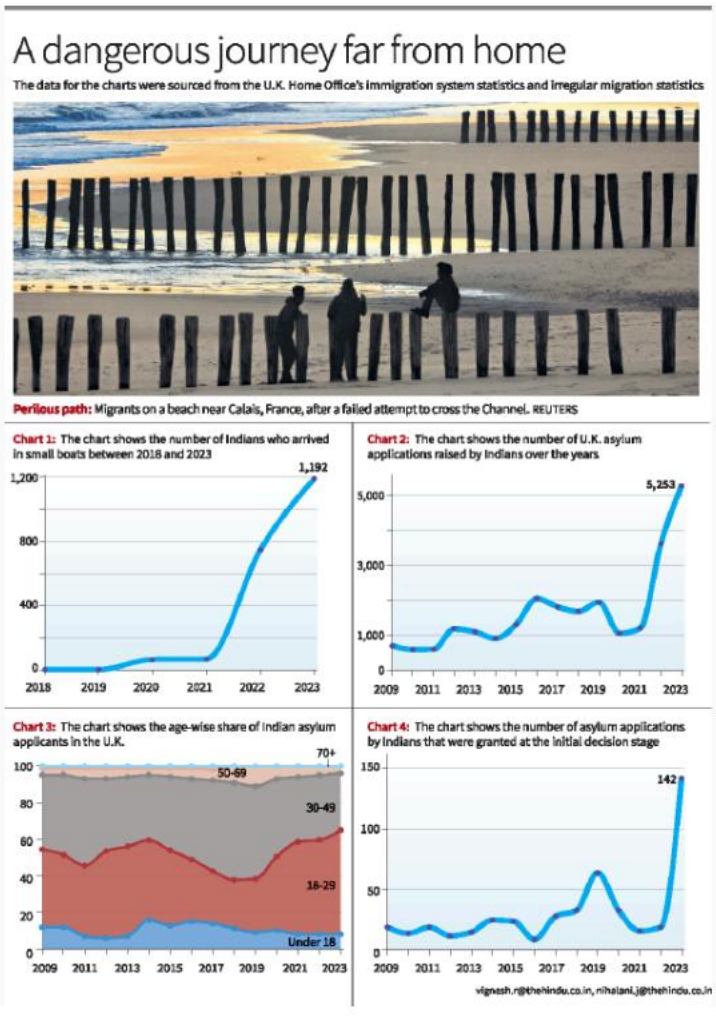

डेटा बिंदु

2023 में 1,000 से अधिक भारतीय अवैध रूप से ब्रिटेन में दाखिल हुए

The number of Indians applying for asylum in the U.K. crossed the 5,000-mark for the first time in 2023

VIGNESH RADHAKRISHNAN & JASMIN NIHALANI

2023 में, 1,000 से अधिक भारतीयों ने नौकरी की तलाश और शरण की तलाश में यूरोप से इंग्लिश चैनल को छोटी नावों में पार करके यूके पहुंचने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। हाल के वर्षों में इस खतरनाक यात्रा पर जाने वाले भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2023 में यह संख्या पिछले वर्ष से दोगुनी से भी अधिक हो गई। हाल के वर्षों में भारत से 18-29 आयु वर्ग के अवैध प्रवासियों की हिस्सेदारी बढ़ी है; वे 2023 में अवैध भारतीय प्रवासियों की कुल संख्या का लगभग 60% थे। समानांतर में, ब्रिटेन में शरण के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों की संख्या भी हाल के वर्षों में बढ़ी है, 2023 में पहली बार 5,000 का आंकड़ा पार कर गई है। विशेष रूप से हाल ही में अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, 2023 में करीब 1 लाख लोग ऐसा करेंगे।

ब्रिटेन हाल के वर्षों में अवैध प्रवासियों की आमद में अचानक वृद्धि की समस्या से जूझ रहा है। यूरोपीय मुख्य भूमि से छोटी नावों द्वारा ब्रिटेन पहुंचने वाले शरण चाहने वालों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021 और 2022 के अधिकांश समय में, हजारों प्रवासियों द्वारा खतरनाक इंग्लिश चैनल को प्रतिदिन पार करना दर्ज किया गया। हालाँकि पिछले दो वर्षों की तुलना में 2023 में इन क्रॉसिंगों की संख्या में कमी आई, लेकिन ऐसी घटनाओं की घटनाएँ COVID-19 महामारी से पहले देखी गई घटनाओं की तुलना में काफी अधिक रहीं। यह प्रवृत्ति 2024 में भी जारी है, इस वर्ष 27 फरवरी तक 2,000 से अधिक लोग ब्रिटेन में प्रवेश कर चुके हैं।

Chart 1 2018 और 2023 के बीच छोटी नावों में आने वाले भारतीयों की संख्या को दर्शाता है। 2023 में, यूके में प्रवेश करने वालों में से अधिकांश अफगानिस्तान (5,545 लोग), ईरान (3,562), और तुर्की (3,060) से थे। भारतीय 1,192 क्रॉसिंग के साथ सूची में नौवें स्थान पर हैं, जो अल्बानिया और मिस्र के लोगों की संख्या के समान है। 2022 में, अल्बानिया में 12,600 क्रॉसिंग दर्ज की गईं, जो उस वर्ष सबसे अधिक थी, क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था एनीमिया से ग्रस्त हो गई थी, जिससे नौकरियों और मजदूरी पर असर पड़ा था।

Chart 2 पिछले कुछ वर्षों में भारतीयों द्वारा यूके में शरण के लिए उठाए गए आवेदनों की संख्या को दर्शाता है। महामारी के बाद यह संख्या आसमान छू गई, 2023 में 5,253 भारतीयों ने यूके में शरण के लिए आवेदन किया। कुल मिलाकर, पिछले साल दुनिया भर से करीब 84,500 लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया। 9,300 के करीब अफगानिस्तान से थे, सबसे अधिक, उसके बाद ईरान (7,397), पाकिस्तान (5,273), और भारत (5,253) थे।

Chart 3 यूके में भारतीय शरण आवेदकों की आयु-वार हिस्सेदारी को दर्शाता है। महामारी के बाद, 18-29 आयु वर्ग के लोगों की हिस्सेदारी सभी वर्षों में 50% से अधिक थी। 2023 में, शरण चाहने वालों में से 57% इसी आयु वर्ग से थे।

Chart 4 भारतीयों द्वारा शरण आवेदनों की संख्या को दर्शाता है जिन्हें प्रारंभिक चरण में मंजूरी दे दी गई थी। 2023 में, 140 से अधिक भारतीय शरण आवेदकों को या तो सुरक्षा दी गई या रहने के लिए छुट्टी दी गई (वे जो शरणार्थी स्थिति के लिए योग्य नहीं हैं लेकिन उन्हें विभिन्न अन्य कारणों से रहने की अनुमति दी गई है)। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश भारतीय शरण आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया था या आवेदकों ने कुछ समय बाद स्वयं आवेदन वापस ले लिया था।

शरण चाहने वालों की यह बढ़ती लहर अब ब्रिटेन में एक राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि देश में इस साल के अंत में या अगले साल जनवरी की शुरुआत में चुनाव हो सकते हैं। ब्रिटिश प्रधान मंत्री, ऋषि सनक, लंबे समय से "नावों को रोकने" का वादा कर रहे हैं - अंग्रेजी चैनल पार करने वाले अवैध प्रवासियों में हालिया वृद्धि का संदर्भ। यह देखते हुए कि कंजर्वेटिव पार्टी अब तक जनमत सर्वेक्षणों में विपक्षी लेबर पार्टी से काफी अंतर से पीछे रही है, श्री सुनक ब्रिटेन में शरण चाहने वालों को रवांडा भेजने के लिए एक विधेयक पर जोर दे रहे हैं, जिसके नतीजे पर असर पड़ सकता है। चुनावों में उनकी और उनकी पार्टी की सफलता पर।

Machine Translated by Google

व्याख्याता

भारत के परमाणु कार्यक्रम की स्थिति

Why is the core-loading event of the Prototype Fast Breeder Reactor being hailed as a milestone? What does the reactor do? Why has the event taken so long to materialise? What led to the delays? What are small modular reactors?

2 में से 1 अगला चरण: 4 मार्च को तमिलनाडु के कलपक्कम में पीएफबीआर की कोर लोडिंग की शुरुआत पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी। पीटीआई -

Photo:

VASUDEVAN MUKUNTH

THE GIST

- 4 मार्च को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) को कोर-लोड करने की प्रक्रिया की शुरुआत देखी।

- पीएफबीआर एक ऐसी मशीन है जो खपत से अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन करती है। इसके कोर-लोडिंग कार्यक्रम को "मील का पत्थर" माना जा रहा है क्योंकि पीएफबीआर का परिचालन भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण II की शुरुआत को चिह्नित करेगा।

- भारत में पीएफबीआर की गाथा कई देरी, लागत वृद्धि और टूट-फूट से जुड़ी रही है
वादे किए, और कई आलोचक अर्जित किए।

The story so far:

4 मार्च को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कलपक्कम में मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन में स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) को कोर-लोड करने की प्रक्रिया की शुरुआत देखी। उनके कार्यालय के एक बयान में इस अवसर को "भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर" कहा गया।

What is the PFBR?

पीएफबीआर एक ऐसी मशीन है जो खपत से अधिक परमाणु ईंधन का उत्पादन करती है। इसके कोर-लोडिंग कार्यक्रम को "मील का पत्थर" माना जा रहा है क्योंकि पीएफबीआर का परिचालन भारत के तीन-चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के चरण II की शुरुआत को चिह्नित करेगा।

सबसे पहले, भारत ने विखंडनीय सामग्री के रूप में दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) और प्राकृतिक यूरेनियम-238 (यू-238) का उपयोग किया, जिसमें यू-235 की बहुत कम मात्रा होती है। परमाणु विखंडन में, परमाणु का नाभिक एक न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है, अस्थिर करता है और कुछ ऊर्जा छोड़ते हुए दो भागों में टूट जाता है। यदि अस्थिर नाभिक अधिक न्यूट्रॉन छोड़ता है, तो रिएक्टर की सुविधाएं अधिक विखंडन प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए उनका उपयोग करने का प्रयास करेंगी। PHWR में भारी पानी - हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम आइसोटोप वाले पानी के अणु - एक विखंडन प्रतिक्रिया से निकलने वाले न्यूट्रॉन को इतना धीमा कर देते हैं कि वे अन्य U-238 और U-235 नाभिक द्वारा पकड़ लिए जाते हैं और नए विखंडन का कारण बनते हैं। भारी पानी को उबलने से बचाने के लिए उस पर दबाव डाला जाता है। प्रतिक्रियाओं से प्लूटोनियम-239 (पीयू-239) और ऊर्जा उत्पन्न होती है।

केवल U-235, U-238 नहीं, एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रख सकता है, लेकिन चरण I में इसकी पूरी खपत हो जाती है। चरण II में, भारत ऊर्जा उत्पादन के लिए PFBR में U-238 के साथ Pu-239 का उपयोग करेगा, U-233, और अधिक पु-239. परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) ने चरण II को लागू करने के लिए 2003 में भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड (भाविनी) नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना की।

चरण III में, ऊर्जा और यू-233 का उत्पादन करने के लिए रिएक्टरों में पीयू-239 को थोरियम-232 (टीएच-232) के साथ जोड़ा जाएगा। होमी जे.
भाभा ने तीन चरणों वाला कार्यक्रम इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि भारत दुनिया के लगभग एक चौथाई थोरियम की मेजबानी करता है। इन तीन चरणों से देश को परमाणु ऊर्जा में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने की उम्मीद है।

Why was the PFBR delayed?

भारत में पीएफबीआर की गाथा कई देरी, लागत में वृद्धि और टूटे वादों से जुड़ी रही है और इसने कई आलोचकों को जन्म दिया है।

कलपक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर (एफबीटीआर) पीएफबीआर प्रौद्योगिकियों के लिए एक परीक्षण स्थल है। इसका निर्माण 1977 में किया गया था लेकिन भारत के 'स्माइलिंग बुद्धा' परमाणु परीक्षण के खिलाफ प्रतिबंधों ने समृद्ध यूरेनियम (जिसे फ्रांस को वितरित करना था) के ऊपर मिश्रित कार्बाइड ईंधन के उपयोग को मजबूर कर दिया। पूर्व ने बिजली उत्पादन कम कर दिया और परिचालन स्थितियों को बदल दिया। जब तक

Machine Translated by Google

भारत सरकार ने 2003 में पीएफबीआर को हरी झंडी दे दी, एफबीटीआर पर काम करने वाले अधिकांश लोग सेवानिवृत्ति के करीब थे या पूरी कर चुके थे।

इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (आईजीसीएआर), कलपक्कम ने पीएफबीआर को डिजाइन किया। इसकी मूल लागत ₹3,492 करोड़ थी और मूल समय सीमा, 2010 थी। छह साल बाद, डीएई ने अधिक धनराशि और एक विस्तारित समय सीमा की मांग की, जिसे सरकार ने 2012 में - ₹5,677 करोड़ और मार्च 2015 तक वाणिज्यिक संचालन प्रदान किया। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान आगे समय सीमा को अगले वर्ष, फिर उसके अगले वर्ष और इसी तरह मार्च 2020 तक बढ़ा दिया गया, व्यावसायीकरण की नई समय सीमा अक्टूबर 2022 थी। यहां तक कि 2019 तक, इसकी लागत बढ़कर ₹6,800 करोड़ हो गई थी। 2014 के ऑडिट में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने पाया कि भाविनी ने न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पर अत्यधिक निर्भर होकर कुछ पीएफबीआर घटकों की खरीद में गड़बड़ी की थी। परिणाम: सौ खरीद आदेशों की नियुक्ति में "औसत देरी" हुई थी। प्रति ऑर्डर 158 दिनों का। देरी के अन्य कारणों में रिएक्टर शीतलक के साथ तकनीकी कठिनाइयाँ शामिल थीं।

How does the PFBR work?

पीएचडब्ल्यूआर विखंडनीय सामग्री के रूप में प्राकृतिक या कम समृद्ध यू-238 का उपयोग करते हैं और उपोत्पाद के रूप में पीयू-239 का उत्पादन करते हैं। इस पीयू-239 को अधिक यू-238 के साथ मिश्रित ऑक्साइड में मिलाया जाता है और एक ब्रीडर कंबल के साथ एक नए रिएक्टर के कोर में लोड किया जाता है। यह एक ऐसी सामग्री है जिसके साथ कोर में विखंडन उत्पाद प्रतिक्रिया करके अधिक पु-239 उत्पन्न करते हैं। ब्रीडर रिएक्टर एक परमाणु रिएक्टर है जो खपत से अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करता है। एक 'तेज़' ब्रीडर रिएक्टर में, न्यूट्रॉन धीमा नहीं होते हैं, जिससे वे विशिष्ट विखंडन प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकते हैं।

पीएफबीआर को खपत से अधिक पीयू-239 का उत्पादन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दो सर्किटों में शीतलक के रूप में तरल सोडियम, एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील पदार्थ का उपयोग करता है। पहले सर्किट में शीतलक रिएक्टर में प्रवेश करता है और (गर्मी) ऊर्जा और रेडियोधर्मिता के साथ निकल जाता है। हीट-एक्सचेंजर्स के माध्यम से, यह केवल गर्मी को द्वितीयक सर्किट में शीतलक में स्थानांतरित करता है। उत्तरार्द्ध बिजली का उत्पादन करने के लिए जनरेटर को गर्मी स्थानांतरित करता है। 2020 के एक पेपर में, IGCAR के पूर्व वैज्ञानिक आरडी काले ने इस प्रणाली को उम्मीद के मुताबिक काम करने से संबंधित कई मुद्दों के बारे में लिखा था। उदाहरण के लिए, उनके अनुसार, पीएफबीआर के साथ काम करने वाले कर्मियों को उम्मीद थी कि सैद्धांतिक गणना और मॉक-अप के साथ परीक्षणों के आधार पर रिएक्टर पोत को लगभग एक महीने में 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा सकता है। लेकिन हकीकत में इस प्रक्रिया में एक साल से अधिक का समय लग गया।

What role can SMRs play?

देरी के कारण छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के रूप में एक और संभावित जटिलता सामने आई। इन रिएक्टर डिज़ाइनों की अधिकतम क्षमता 300 मेगावाट है, इसके लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है, और अधिक सुरक्षा सुविधाओं को समायोजित किया जाता है।

"कई देश पारंपरिक [सुविधाओं] के पूरक के लिए एसएमआर विकसित कर रहे हैं क्योंकि एसएमआर को ब्राउनफील्ड साइटों में बुनियादी ढांचे का पुनरुत्पादन करके कम लागत और समय पर स्थापित किया जा सकता है," नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज, बेंगलुरु के प्रोफेसर आर. श्रीकांत ने आयात से बताया अमेरिका अपने 123 समझौते के माध्यम से। उनके अनुसार, एसएमआर के योगदान को बढ़ाने के लिए, अन्य बातों हिंदू · उन्होंने कहा कि एसएमआर कम-संवर्धित यूरेनियम के साथ काम कर सकते हैं, जो भारत कर सकता है के अलावा, परमाणु ऊर्जा नियामक निकाय (एईआरबी) की देखरेख में निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम (1962) और अन्य संबंधित क़ानूनों में संशोधन की आवश्यकता होगी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के अनुसार परमाणु ईंधन और अपशिष्ट दोनों को डीएई द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

What is the value of stage II?

पीएफबीआर की क्षमता 500 मेगावाट है। 2019 में, डीएई ने 600 मेगावाट क्षमता के चार और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) बनाने का प्रस्ताव रखा - 2021 से कलपक्कम में दो और 2025 से दो, चयनित साइटों के साथ। विशेषज्ञों ने कहा है कि चरण II प्रौद्योगिकियों पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका रिएक्टरों को वाणिज्यिक सेवा में धकेलना है।

हालाँकि, देरी से मदद नहीं मिली है। 2003 में, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्षितिज पर एक झटका थे। आज, सौर ऊर्जा का शुल्क ₹2.5/kWh से कम है जबकि परमाणु बिजली की लागत लगभग ₹4/kWh है। 2011 की फुकुशिमा दाइची आपदा ने भी दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के खिलाफ जनता की राय बदल दी, जिससे नई सुविधाओं पर काम धीमा हो गया। भारत पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने, जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करने और अपने नवीकरणीय क्षेत्र को कुछ राहत देने के दबाव के कारण आज परमाणु ऊर्जा को एक नया जीवन मिला है। एनपीसीआईएल के अध्यक्ष बीसी पाठक ने बताया कि निगम की 2024 से "हर साल एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर चालू करने" की योजना है।
हिंदू

What are the challenges of stage II?

दूसरी ओर, बड़ी चुनौतियाँ इंतज़ार में हैं। अन्य रिएक्टर डिज़ाइनों की तुलना में एफबीआर को संभालना कठिन है, जबकि डीएई ने सुरक्षा चिंताओं के प्रति अपनी अक्सर कठोर प्रतिक्रिया के कारण प्रतिकूल सार्वजनिक प्रतिष्ठा हासिल कर ली है।

इसके अलावा, नागरिक परमाणु कार्यक्रम की नोडल नियामक संस्था, एईआरबी, कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित की गई थी और अंततः डीएई सचिव को रिपोर्ट करती है। 2015 में, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने भारत से एक स्वतंत्र वैधानिक परमाणु नियामक स्थापित करने का आग्रह किया।

डीएई ने 2011 में परमाणु सुरक्षा नियामक प्राधिकरण (एनएसआरए) विधेयक के साथ इसी तरह की चिंताओं का जवाब दिया था। इसमें एईआरबी को एनएसआरए से बदलने की मांग की गई थी। लेकिन एनएसआरए की संरचना पर केंद्र सरकार को बहुत अधिक नियंत्रण की अनुमति देने के लिए इसकी आलोचना की गई।

अंत में, अन्य उत्पादों के बीच, थोरियम ईंधन चक्र सीज़ियम-137, एक्टिनियम-227, रेडियम-224, रेडियम-228, और थोरियम-230 का उत्पादन करता है - ये सभी आइसोटोप रेडियोधर्मी हैं जो उनके प्रबंधन और भंडारण को जटिल बनाते हैं।

Machine Translated by Google

जमानत कानून और दिशानिर्देशों में सुधार का मामला, लेकिन पहले सही निदान करें

A large number of undertrials continue to remain in prison despite being granted bail due to challenges in complying with bail conditions. Lack of means to arrange for money/property and local sureties are the most significant reasons accounting for the inability to comply with bail conditions

- Photo: Getty Images

MEDHA DEO, MAYANK LABH,

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जमानत है और जेल और जमानत नियम बनता जा रहा है। मयंक लाभ इस लेख के प्रति बढ़ती अनिच्छा, परीक्षण न्यायाधीशों की भाग पर हैं। को अनुदान न देने से विचाराधीन कैदियों को जमानत देने का प्रश्न और भी जटिल हो गया है, जिनमें से अधिकांश दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ 26, 2024 दिनांकित जुलाई मेधा और डियो जमानत के लिए बांड/पैसे लेना जरूरी है।

को

भारत की जेलों में 75% से अधिक कैदी विचाराधीन कैदी हैं जबकि भारतीय जेलों में कैदियों की संख्या 118% है। ये एकदम भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में संकट के पैमाने को दर्शाने के लिए अक्सर वास्तविकताओं का हवाला दिया जाता है। का सर्वोच्च न्यायालय भारत ने हाल ही में भारत की जमानत प्रणाली और इसकी अपर्याप्तता को स्वीकार किया है SatenderKumar अंतिल CBIvs , इस संकट में योगदान. कोर्ट ने कहा कि जमानत कानून पर बार-बार दिशा-निर्देश देने के बावजूद चीजें ज्यादा नहीं बदली हैं जमीन पर। न्यायालय ने जमानत से संबंधित कानूनों पर व्यापक दिशानिर्देश प्रदान किए, जैसे कि समयसीमा अनिवार्य करना जमानत अर्जियों के निस्तारण और अलग से कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया। निर्णय नोट किया गया विचाराधीन कैदियों की जेलों में भीड़ ने 'निर्दोषता की धारणा' और 'जमानत जेल नहीं' के सिद्धांत की अनदेखी की आदर्श होना चाहिए. हालाँकि, अभी भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि इन स्थापित सिद्धांतों को अधिक सम्मान क्यों दिया जाता है पालन की अपेक्षा उनका उल्लंघन।

जमानत पर कानून की किसी भी पुनर्कल्पना के लिए पहले उस समस्या की सटीक प्रकृति को समझने की जरूरत है जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर विचाराधीन कैदियों को जेल में डाल दिया जाता है। यह मूल्यांकन कई मापदंडों पर आधारित होना चाहिए और हमारे पास कोई वास्तविकता नहीं है इनमें से प्रत्येक मुद्दे को कैसे प्रभावित करता है, इस पर अनुभवजन्य साक्ष्य। किस अनुपात में विचाराधीन कैदी जमानत के लिए आवेदन कर रहे हैं? क्या किस अनुपात में जमानत आवेदन स्वीकार या खारिज किये जाते हैं और किस आधार पर? क्या जमानत अनुपालन कहीं अधिक बड़ी समस्या है जमानत से इनकार से? ये कुछ मौलिक अनुभवजन्य प्रश्न हैं जिनका उत्तर आवश्यक है। एक प्रभावी जमानत कानून अवश्य होना चाहिए विचाराधीन कैदियों की जनसांख्यिकी, श्रेणी जैसे चर के साथ इन उत्तरों के सहसंबंध पर आधारित होना चाहिए अपराध और जमानत के लिए समय-सीमा, और सामाजिक-आर्थिक और संरचनात्मक बाधाओं का भी समाधान। की नींव वर्तमान जमानत कानून यह सुनिश्चित करता है कि यह गरीब विरोधी है और हाशिए की पृष्ठभूमि के लोगों पर असंगत रूप से बोझ डालता है। हम जो समाधान तैयार करना चाहते हैं वह समस्या की यथार्थवादी समझ पर आधारित होना चाहिए।

Lack of safeguards

न्यायालय ने कहा कि मनमानी गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने से तलाश करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी अदालतों से जमानत. हालाँकि, ये सुरक्षा उपाय गिरफ्तार व्यक्तियों के एक महत्वपूर्ण अनुपात को बाहर कर देते हैं, विशेषकर उन लोगों को समाज के वंचित वर्गों से, जो विचाराधीन कैदियों का बड़ा हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए, की गिरफ्तारी किसी व्यक्ति को 'आवश्यक' के रूप में उचित ठहराया जाता है यदि पुलिस के पास 'विश्वास करने के कारण' हैं कि उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना आवश्यक है अदालत। इस तरह के अस्पष्ट औचित्य प्रवासियों, बिना संपत्ति वाले व्यक्तियों या परिवार से संपर्क न रखने वाले लोगों को अधिक जोखिम में डालते हैं उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के कारण गिरफ्तारी। यरवदा और नागपुर में निष्पक्ष परीक्षण कार्यक्रम (एफटीपी) से डेटा केंद्रीय जेलें यहां शिक्षाप्रद हो सकती हैं। एफटीपी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए विचाराधीन कैदियों (2,313) में से 93.48% के पास कोई संपत्ति नहीं थी, 62.22% का , 18.50% प्रवासी थे, परिवार के साथ कोई संपर्क नहीं था, और 10% का पूर्व इतिहास था क़ैद. जाहिर है, नमूने के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अनुचित तरीके से सुरक्षा से बाहर रखा जाएगा गिरफ्तारी के खिलाफ और हमारी जेलों में विचाराधीन कैदियों के बड़े अनुपात में योगदान।

Approach to bail adjudication

जमानत देने की शक्ति काफी हद तक अदालत के विवेक पर आधारित है और प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करती है। उच्चतम जमानत पर निर्णय लेने में अदालतों द्वारा इस तरह के विवेक के प्रयोग को निर्देशित करने के लिए न्यायालय ने बार-बार सिद्धांत निर्धारित किए हैं अनुप्रयोग। हालाँकि ये दिशानिर्देश आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, लेकिन वे इनकार को भी मान्य करते हैं अपराध की गंभीरता, आरोपी के चरित्र आदि के आधार पर जमानत या कठिन जमानत की शर्तें लगाना आरोपी के फरार होने या सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना। ऐसे सभी मामलों में, अदालतें शायद ही कभी अपना काम करती हैं जमानत देने के लिए विवेकाधिकार और जमानत पर रिहाई के खिलाफ अधिक सख्त रुख अपनाने की संभावना है। विद्यमान होने के बावजूद दिशानिर्देश, अदालतें आमतौर पर जमानत खारिज करने के कारणों को दर्ज नहीं करती हैं; जमानत आवेदनों पर निर्णय लेने में अदालतें अपराध-आधारित और व्यक्ति-आधारित विचारों को किस प्रकार ध्यान में रखती हैं, इसके पीछे तर्क स्पष्ट नहीं है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हाशिए पर रहने वाले लोगों को इन व्यापक अपवादों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। या तो उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया जाता है या उनकी वास्तविकताओं की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कठिन शर्तों के साथ जमानत दे दी गई। नकदी की प्रकृति में जमानत की शर्तें बांड, ज़मानत बांड, संपत्ति के स्वामित्व और शोधनक्षमता का प्रमाण, जैसा कि आम बात है, वास्तविकता के विपरीत हैं जेलों में बंद विचाराधीन कैदी।

Challenges in bail compliance

अनुपालन में चुनौतियों के कारण जमानत मिलने के बावजूद बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी अभी भी जेल में हैं जमानत शर्तों के साथ. धन/संपत्ति की व्यवस्था करने के साधनों की कमी और स्थानीय ज़मानत सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं एक विचाराधीन कैदी की जमानत शर्तों का पालन करने में असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, एफ़टीपी में हमारे अनुभव से उत्पन्न वास्तविकताएँ। हालाँकि, निवास और पहचान प्रमाण की कमी, परिवार द्वारा परित्याग और आवागमन में सीमाएँ जैसे कारक अदालती व्यवस्था किसी विचाराधीन कैदी की जमानत शर्तों का पालन करने की क्षमता को भी कमजोर कर देती है। जमानत शर्तों का अनुपालन और अत्यधिक संरचनात्मक रूप से वंचित विचाराधीन कैदियों के लिए अदालतों में उपस्थिति सुनिश्चित करना निरंतर आवश्यक है हैंडहोल्डिंग, जैसा कि पिछले तीन वर्षों में एफ़टीपी के हस्तक्षेप से स्पष्ट है। यह अंतिम सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है न्याय की मील डिलीवरी जिस पर मौजूदा जमानत कानून विचार नहीं करता है।

हमारा अनुभव बताता है कि 14% मामलों में, विचाराधीन कैदी जमानत की शर्तों का पालन करने में असमर्थ रहे और जेल में ही बने रहे जमानत मिलने के बावजूद जेल। इनमें से लगभग 35% मामलों में जमानत मिलने में एक महीने से अधिक का समय लग गया विचाराधीन कैदियों को जमानत की शर्तों का पालन करना होगा और उनकी रिहाई सुनिश्चित करनी होगी।

Flawed assumptions

जमानत प्रणाली, जैसा कि वर्तमान में चल रही है, में त्रुटिपूर्ण धारणाएं हैं कि प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति के पास संपत्ति होगी या होगी संपत्तियुक्त सामाजिक संपर्कों तक पहुंच। यह माना जाता है कि उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय हानि का जोखिम आवश्यक है अदालत में आरोपी की. ऐसी धारणाओं का प्रभाव 'जेल नहीं जमानत' के नियम को निरर्थक बना देना है विचाराधीन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण अनुपात। किसी भी जमानत कानून को प्रभावी ढंग से राहत प्रदान करने के लिए, सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन करना आवश्यक है कहा कि अनुमान अनिवार्य है। जमानत सुधार की तत्काल आवश्यकता है लेकिन यह प्रतिकूल होगा पहले समस्या को समझने और उसका निदान करने का आधार विकसित किए बिना सुधार कार्य शुरू करें।

मेधा और डियो Mayank Labh हैं साथ गोरा परीक्षण कार्यक्रम, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में विचाराधीनकैदियों को कानूनी परियोजना 39ए, सहायता पहल। यह कार्यक्रम पुणे और नागपुर केंद्रीय जेलों में विचाराधीन कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करता है

Machine Translated by Google

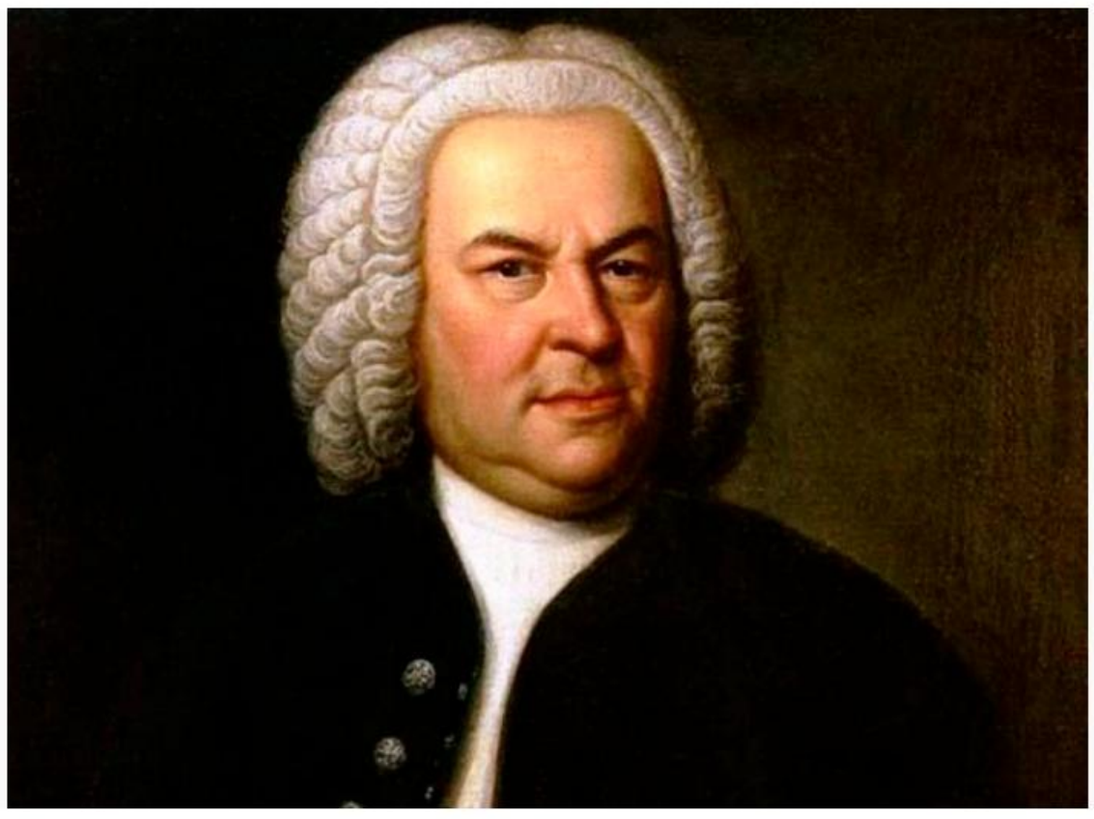

कृपया अपने उत्तर यहां भेजें

dailyquiz@thehindu.co.in

THE DAILY QUIZ

महानतम बारोक संगीतकारों में से एक एंटोनियो विवाल्डी पर एक प्रश्नोत्तरी, जिनका जन्म 4 मार्च को हुआ था, 1678

दृश्य प्रश्न:

इस प्रसिद्ध संगीतकार का नाम बताइए, जिसने 1713 और 1714 के बीच कीबोर्ड, स्ट्रिंग्स, ऑर्गन और हार्पसीकोर्ड के लिए विवाल्डी के कम से कम नौ संगीत कार्यक्रम लिखे।

V.V. RAMANAN

Question 1

एंटोनियो विवाल्डी को 'रेड प्रीस्ट' उपनाम क्यों दिया गया?

Question 2

विवाल्डी को 1703 में एक पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने 'स्ट्रेटेज़ा डि पेट्टो' से पीड़ित होने के कारण पुजारी के रूप में कार्य नहीं किया। इस बीमारी की क्या व्याख्या की गई है?

Question 3

संगीतकार ने अपने जीवन के 37 वर्ष पियो ओस्पेडेल डेला पिएटा शरण में एक संगीत शिक्षक/निर्देशक के रूप में बिताए और उनकी अधिकांश रचनाएँ उसी कार्यकाल के दौरान थीं। उस आश्रम में किस प्रकार के कैदियों को रखा गया था?

Question 4

उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएँ 1718-1720 के आसपास लिखी गईं जब विवाल्डी मंटुआ में कोर्ट चैपल मास्टर थे। चार संगीत कार्यक्रमों के इस समूह का नाम बताएं और वे किस वाद्ययंत्र के लिए लिखे गए थे?

Question 5

यदि मोजार्ट की रचनाओं के आगे 'K' (कोचेल कैटलॉग के लिए) लगाया जाता है, तो आज विवाल्डी की रचनाओं को किन दो अक्षरों से पहचाना जाता है?

Questions and Answers to the previous day's daily quiz:

1: [illegible] बीमारी है। **Ans: RPI Deficiency.**

2: फिल्म पर इस दुर्लभ बीमारी के आसपास बनाया गया था। **Ans: Hutchinson Gilford Progeria Syndrome. Or, merely Progeria, which causes premature ageing.**

3: एक भाषण विकार जिसके कारण देशी वक्ता 'विदेशी' लहजे में बात करता है। **Ans. Foreign Accent Syndrome. It is often caused by damage to the brain.**

4: इस दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों का खून नीले रंग का होता है। **Ans: Methemoglobinemia, a blood disorder in which an abnormal amount of methemoglobin, a form of haemoglobin, is produced.**

5: स्टोन मैन रोग की परिभाषा. **Ans: It transforms a person's muscle tissues into bones, and is also known as Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP).**

दृश्य: न्यू गिनी में जनजातियों के बीच यह दुर्लभ बीमारी अपने आप समाप्त हो गई जब उनके बीच की इस विशेष आदत को समाप्त कर दिया गया। **Ans: Kuru disease. It is an acquired infectious disease linked with the ritualistic practice of feeding upon the corpses of relatives as part of mourning. Putting an end to the practice meant an end to the disease as well.**

Early Birds: K.N. Viswanathan| Rajmohan. V| M. Suresh Kumar| Sanjana Veerabhadra

Machine Translated by Google

एसबीआई ने चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा है

The SC had told the bank to furnish the information to the Election Commission by March 6; SBI said there were practical difficulties with the decoding exercise and the timeline fixed for it

एसबीआई द्वारा मांगे गए समय विस्तार से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि विवरण लोकसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक किया जाएगा। रॉयटर्स - Photo: - Photo:

THE HINDU BUREAU
नई दिल्ली

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण, खरीद की तारीख, नाम सहित सार्वजनिक करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा। खरीदार, और बांड का मूल्य।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने 15 फरवरी को चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से मनमाना" बताते हुए रद्द कर दिया था, जो राजनीतिक दलों को वित्तीय योगदान के लिए गुमनामी प्रदान करती थी।

Full disclosure

बैंक को चुनाव आयोग (ईसी) को उन राजनीतिक दलों के बारे में पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने 12 अप्रैल, 2019 से योगदान प्राप्त किया था और चुनावी बांड भुनाया था। बैंक को 6 मार्च तक चुनाव आयोग को जानकारी प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। बदले में, पोल बॉडी को एसबीआई द्वारा दी गई पूरी जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी।

एसबीआई द्वारा मांगे गए समय विस्तार से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि विवरण लोकसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक किया जाएगा।

अपने नौ पन्नों के आवेदन में, बैंक ने कहा कि "डिकोडिंग अभ्यास और इसके लिए तय की गई समयसीमा में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ थीं"।

एसबीआई ने प्रस्तुत किया, "यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए कड़े उपायों के कारण कि दानदाताओं की पहचान गुमनाम रखी जाए, चुनावी बांड को डिकोड करना और दानकर्ता का दान से मिलान करना एक जटिल प्रक्रिया होगी।"

बैंक ने पूरे भारत में 29 अधिकृत शाखाओं के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित की है और कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं रखा गया है। दाता का विवरण निर्दिष्ट शाखाओं में एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था।

“दाता की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए, प्रत्येक बांड के जारी होने की तारीख को किसी विशेष दाता द्वारा खरीद की तारीख के साथ जांचना और मिलान करना होगा। यह अभ्यास केवल सूचना के प्रथम साइलो से निपटेगा।

इन बांडों को राजनीतिक दलों द्वारा अपने निर्दिष्ट बैंक खातों में भुनाया गया था। तदनुसार, इस जानकारी को बांड मोचन जानकारी के साथ मिलान करना होगा जो दूसरे साइलो को बनाती है, ”बैंक ने समझाया।

इसमें कहा गया है कि अदालत द्वारा सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया विवरण अलग से संग्रहीत किया गया था।

“कुछ विवरण जैसे बांड की संख्या आदि को डिजिटल रूप से संग्रहीत किया जाता है, जबकि विवरण के अन्य सेट को भौतिक रूप से संग्रहीत किया जाता है। सभी विवरणों को डिजिटल रूप से संग्रहीत नहीं करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि इसे आसानी से एकत्र नहीं किया जा सके, ”आवेदन में कहा गया है।

Machine Translated by Google

क्या आप स्पैम या धोखाधड़ी कॉल से थक गए हैं? चक्षु पर मुकदमा दायर करो

अश्विनी वैष्णव

THE HINDU BUREAU
नई दिल्ली

दूरसंचार विभाग (DoT) ने सोमवार को धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट लॉन्च की। यह , दूरसंचार उपयोगकर्ताओं के लिए एक मंच सुविधा, संदिग्ध धोखाधड़ी संचार की रिपोर्ट पर उपलब्ध है", DoT ने अपनी घोषणा चक्षुसंचारसाथी.gov.in/sfc , नागरिकों को "सक्रिय रूप से" की अनुमति देगा में कहा।

प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को बैंक खाते, भुगतान वॉलेट, सिम, गैस कनेक्शन से संबंधित धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने की अनुमति देगा। बिजली कनेक्शन, केवाईसी अद्यतन, समाप्ति, निष्क्रियता, सरकारी अधिकारी या रिश्तेदार के रूप में प्रतिरूपण, और सेक्सटॉर्शन.

डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म भी लॉन्च किया गया, जो एक गैर-सार्वजनिक डेटा-साझाकरण संसाधन होगा "दूरसंचार सेवा प्रदाता, कानून प्रवर्तन एजेंसियां, बैंक और वित्तीय संस्थान, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पहचान दस्तावेज़ जारी करने वाले प्राधिकारी, इत्यादि", DoT ने कहा।

संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी कॉलर का समर्थन किया नाम प्रस्तुति (सीएनएपी), एक ऐसी सुविधा जो सेवा का विकल्प चुनने वाले दूरसंचार उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत देखने की अनुमति देगी उन्हें बुलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम. दूरसंचार कंपनियों और कुछ नागरिक समाज समूहों ने चेतावनी दी थी कि इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा लोगों की निजता के अधिकार पर प्रभाव।

श्री वैष्णव ने यह जानने के लिए कि दरवाजा कौन खटखटा रहा है, फीचर की तुलना दाईं ओर से की, लेकिन इसे जोड़ा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा सीएनएपी की शुरूआत के पक्ष में की गई सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी आगे कदम उठाने से पहले विस्तार से।

Machine Translated by Google

जो बिडेन, डोनाल्ड ट्रम्प सुपर मंगलवार को प्राथमिक दौड़ जीतने के लिए तैयार हैं

उम्मीद है कि डोनाल्ड ट्रम्प मंगलवार को रिपब्लिकन मुकाबलों में जीत हासिल करेंगे, जबकि निक्की हेली ने अब तक केवल एक ही रेस जीती है। एएफपी - Photo:

SRIRAM LAKSHMAN
वाशिंगटन डीसी

राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों ने इस साल सुपर ट्यूजडे से पहले देश भर में धावा बोल दिया, जब 17 अमेरिकी राज्यों और क्षेत्रों में नवंबर के आम चुनाव के लिए अपने दावेदारों को चुनने के लिए प्राइमरी और कॉकस का आयोजन किया गया। प्रत्येक पार्टी के एक तिहाई से अधिक प्रतिनिधियों (यानी, प्रतिनिधि जो उम्मीदवार का चयन करने के लिए पार्टियों के सम्मेलनों में मतदान करते हैं) का समर्थन मंगलवार को मिलने वाला है।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के मंगलवार को रिपब्लिकन मुकाबलों में जीत हासिल करने की उम्मीद है, संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने अब तक केवल एक ही रेस जीती है (वाशिंगटन डीसी)। हालाँकि, इस स्तर पर, बिडेन-ट्रम्प का टकराव लगभग निश्चित है, मार्च और अप्रैल में राज्यों के समूहों के मतदान के साथ, अगले हफ्तों के लिए आगे के अभियान की योजना बनाई गई है।

वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, कई राज्यों में डेमोक्रेटिक (पुनः) नामांकन के लिए निर्विरोध दौड़ रहे हैं, जबकि कुछ राज्यों में स्वयं सहायता लेखक मैरिएन विलियमसन और मिनेसोटा कांग्रेसी डीन फिलिप्स जैसे अन्य प्रतियोगी होंगे।

Challenging days

इसलिए श्री बिडेन के मंगलवार के दिन जीतने की उम्मीद है, लेकिन इस प्रक्रिया से पता चला है कि व्हाइट हाउस के लिए अंतिम रास्ता - जब प्राइमरी पूरी हो जाएंगी और श्री बिडेन संभवतः श्री ट्रम्प का सामना करेंगे - श्री बिडेन के लिए कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। दूसरे कार्यकाल की चाह रखने वाले मौजूदा राष्ट्रपति के मामले में अक्सर ऐसा होता है। श्रीमान के बारे में प्रश्न

बिडेन की उम्र, अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति के बारे में धारणाएं और श्री बिडेन का इज़राइल-हमास संघर्ष से निपटने का तरीका उनके खिलाफ काम कर रहा है।

श्री बिडेन को सप्ताहांत में निराशाजनक मतदान परिणामों का सामना करना पड़ा। ए/सिएना कॉलेज सर्वेक्षण ने संकेत दिया कि राष्ट्रपति की श्री ट्रम्प के 48% के मुकाबले 43% पंजीकृत मतदाताओं का समर्थन प्राप्त था। 2020 में श्री बिडेन को वोट देने वालों में से लगभग 10% 2024 में श्री ट्रम्प को वोट देने की योजना बना रहे थे। सर्वेक्षण के अनुसार, डेमोक्रेटिक प्राथमिक मतदाता कमोबेश इस बात पर समान रूप से विभाजित थे कि श्री बिडेन को उनकी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए या नहीं। इस विचार का सबसे कड़ा विरोध 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों ने किया। डेटा ने यह भी संकेत दिया कि गैर-श्वेत गैर-कॉलेज स्नातकों के बीच श्री ट्रम्प पर श्री बिडेन की बढ़त भी 2020 के बाद से काफी कम हो गई है।

डेमोक्रेटिक राजनेताओं ने मिशिगन के महत्वपूर्ण राज्य में प्राथमिक मतदाताओं से गाजा पर इज़राइल के जवाबी हमलों के प्रति श्री बिडेन की नीति के प्रति अपनी निराशा दिखाने का आग्रह किया, जिसमें 30,000 से अधिक लोगों की जान चली गई, 1,00,000 से अधिक मिशीगन वासियों ने 'अप्रतिबद्ध' मतदान किया। पिछले सप्ताह का डेमोक्रेटिक प्राइमरी।

यह 10,000 अप्रतिबद्ध वोटों के लक्ष्य से अधिक था और पिछले दो राष्ट्रपति चुनावों में ऐसे वोटों की संख्या का लगभग पांच गुना था और इसे श्री बिडेन को इज़राइल के प्रति अपने उदार रुख को बदलने की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। यदि प्रशासन यथास्थिति जारी रखता है तो मतदाताओं की बढ़ती संख्या, न केवल मुस्लिम अमेरिकी, बल्कि पूरे बोर्ड में युवा मतदाता भी, चुनाव के दिन घर पर बैठ सकते हैं। कुछ हज़ार मतदाता बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं: श्री ट्रम्प ने 2016 में मिशिगन में पूर्व डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को 11,000 से भी कम वोटों से हराया और श्री बिडेन ने 2020 में श्री ट्रम्प से 2.8% के अंतर से राज्य जीता। 1,54,000 वोट)।

Call for ceasefire

रविवार को, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने क्षेत्र में तत्काल युद्धविराम और हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की वापसी का आह्वान किया। सोमवार को उनका इजरायली युद्ध कैबिनेट सदस्य बेनी गैंट्ज़ से मिलने का कार्यक्रम था।

श्री ट्रम्प ने अब तक 247 प्रतिनिधियों को जीत लिया है - जो सुश्री हेली की तुलना में 10 गुना अधिक है। अब तक उनकी कानूनी परेशानियां श्री ट्रम्प को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाई हैं और उन्होंने खुद को राजनीतिक जादू-टोना के शिकार के रूप में चित्रित करने के लिए अपने अभियान रैलियों में उनका इस्तेमाल किया है।

ट्रम्प कैबिनेट में काम कर चुकीं सुश्री हेली ने कहा है कि जब तक वह "प्रतिस्पर्धी" हैं, तब तक वह दौड़ में बनी रहेंगी, लेकिन उन्होंने इस शब्द को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कॉलेज स्नातकों और स्वतंत्र मतदाताओं के साथ-साथ उन लोगों के बीच भी कुछ आकर्षण दिखाया है जो खुद को उदारवादी मानते हैं।

जबकि उन्होंने दावा किया है कि वह ट्रम्प विरोधी नहीं हैं, सुपर मंगलवार से पहले सुश्री हेली के अपने पूर्व बॉस पर हमले तेज़ हो गए हैं। उन्होंने सुझाव दिया है कि दोनों प्रमुख उम्मीदवार नौकरी के लिए बहुत बूढ़े हैं, उन्होंने राजकोषीय घाटे और खर्च की ओर इशारा किया है - विशेष रूप से व्हाइट हाउस में श्री ट्रम्प के समय के दौरान और उनकी अलगाववादी 'विदेश नीति और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए प्रशंसा' की आलोचना की है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सुश्री हेली से श्री ट्रम्प के चुने हुए जीओपी उम्मीदवार होने की प्रतिज्ञा के बारे में सवाल किया गया, जो सभी जीओपी उम्मीदवारों को एक अंतर-पार्टी बहस से पहले लेनी पड़ी थी कि वे अंतिम उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने उनका समर्थन करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई। उन्होंने पार्टी संगठन में बदलाव का हवाला दिया, विशेष रूप से रिपब्लिकन नेशनल कमेटी (आरएनसी) के सह-अध्यक्ष पद के लिए श्री ट्रम्प की बहू लारा ट्रम्प की बोली का हवाला दिया। उन्होंने रविवार को एनबीसी को बताया, "आरएनसी अब वही आरएनसी नहीं है, अब यह ट्रम्प की बहू है।" उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि निर्वाचित होने पर श्री ट्रम्प देश के संविधान का पालन करेंगे या नहीं।

मिलना प्रेस

सुपर मंगलवार को कई 'डाउन बैलट' प्राइमरीज़ भी होती हैं - जैसे कि गवर्नर (उत्तरी कैरोलिना) के पद के लिए प्राथमिक प्रतियोगिता, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए कई प्राथमिक प्रतियोगिताएं, जहां रिपब्लिकन के पास चार सीटों वाला बहुमत है, और अमेरिकी सीनेट.

Machine Translated by Google

Seamless payments

RBI asks NBBL to create system that facilitates easier online payments for merchants via customers' netbanking facility

- The RBI had envisaged an interoperable system since it is difficult for banks to integrate with multiple payment aggregators
- Currently, a bank is required to separately integrate with each payment aggregator of different online merchants

- Internet Banking is preferred for payments like income tax, insurance premium, mutual fund investments, etc.

RBI ने NBBL को यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि 2024 में नेट बैंकिंग इंटरऑपरेबल हो

The new system is expected to facilitate quicker settlement of funds for merchants; right now, a customer wanting to make a payment from a bank account to a merchant needs the bank to have an existing arrangement with the merchant's PA

THE HINDU BUREAU
मुंबई

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने व्यापारियों के लिए धन के निपटान में तेजी लाने के लिए एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) को इंटरनेट बैंकिंग के लिए एक इंटरऑपरेबल प्रणाली लागू करने का काम सौंपा है और उम्मीद है कि यह प्रणाली वर्तमान कैलेंडर में पेश की जाएगी। वर्ष।

गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा, "आयकर, बीमा प्रीमियम, म्यूचुअल फंड भुगतान और ई-कॉमर्स जैसे भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग एक पसंदीदा माध्यम है।"

"वर्तमान में, पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए) के माध्यम से संसाधित ऐसे लेनदेन इंटरऑपरेबल नहीं हैं, यानी, एक बैंक को अलग-अलग ऑनलाइन व्यापारियों के प्रत्येक पीए के साथ अलग से एकीकृत करने की आवश्यकता होती है। परिणामस्वरूप, यदि कोई ग्राहक अपने बैंक खाते से किसी निश्चित व्यापारी को भुगतान करना चाहता है, तो व्यापारी के पीए और ग्राहक के बैंक के पास एक व्यवस्था होनी चाहिए, "श्री दास ने समझाया।

"पीए की कई संख्या को देखते हुए, प्रत्येक बैंक के लिए प्रत्येक पीए के साथ एकीकृत करना मुश्किल है। इसके अलावा, भुगतान प्रणाली और इन लेनदेन के लिए नियमों के एक सेट की कमी के कारण, व्यापारियों द्वारा भुगतान की वास्तविक प्राप्ति में देरी होती है और निपटान जोखिम होता है, "उन्होंने कहा।

आरबीआई ने पहले इंटरनेट बैंकिंग लेनदेन के लिए एक इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली की परिकल्पना की थी।

"इस उद्देश्य के अनुसरण में, हमने एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड को ऐसी इंटरऑपरेबल प्रणाली लागू करने की मंजूरी दे दी है। हम चालू कैलेंडर वर्ष के दौरान इंटरनेट बैंकिंग के लिए इस इंटरऑपरेबल भुगतान प्रणाली के लॉन्च की उम्मीद करते हैं। नई प्रणाली व्यापारियों के लिए धन के त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करेगी, "उन्होंने कहा।

Machine Translated by Google

'यूक्रेन युद्ध ने माल के निर्यात को धीमा कर दिया'

THE HINDU BUREAU

कोयंबत्तूर

वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव विपुल बंसल ने सोमवार को कहा कि यूक्रेन में युद्ध ने वित्त वर्ष 2024 में माल निर्यात वृद्धि को कम करने में योगदान दिया था, जो पिछले तीन वर्षों में उतना मजबूत नहीं था।

इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (ईईपीसी इंडिया) द्वारा आयोजित इंटरनेशनल इंजीनियरिंग सोर्सिंग शो में बोलते हुए उन्होंने कहा कि निर्यात कई बाहरी कारकों से प्रभावित हुआ है। रत्न और आभूषण जैसे क्षेत्रों से निर्यात यूक्रेन युद्ध से प्रभावित हुआ था, जबकि इंजीनियरिंग निर्यात, जो लगभग 26% था, ने इस वर्ष अपनी संरचना बरकरार रखी थी।

श्री बंसल ने कहा कि 2030 तक 1 ट्रिलियन डॉलर के व्यापारिक निर्यात लक्ष्य के लिए 12% की वृद्धि दर की आवश्यकता है, लेकिन युद्ध जैसी चुनौतियाँ बनी रहती हैं। उन्होंने ईईपीसी से विकास हासिल करने के लिए निर्यात मूल्य श्रृंखला में और अधिक लोगों को जोड़ने का आग्रह किया।

श्री बंसल ने कहा कि पीएलआई योजना को न केवल आयात प्रतिस्थापन में सहायता करनी चाहिए, बल्कि निर्यात बढ़ाने का एक उपकरण भी बनना चाहिए।

Machine Translated by Google

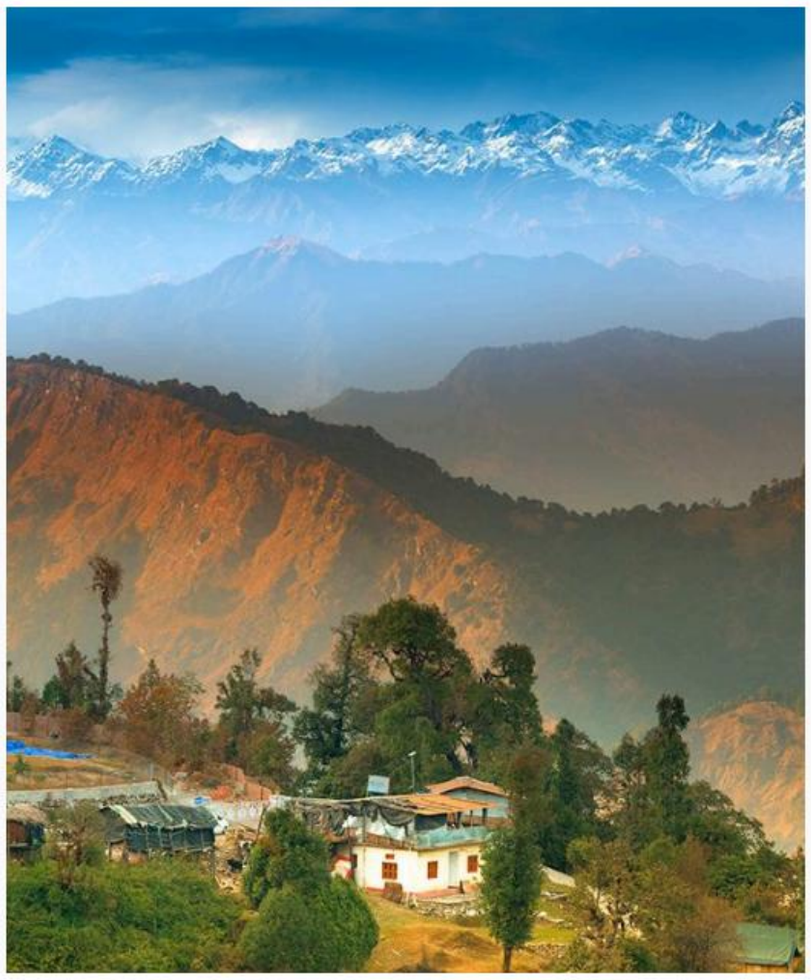

'हिमालय में 3 डिग्री तक साल भर सूखा'

अध्ययन से पता चलता है कि पेरिस समझौते का पालन करके भारत में गर्मी के तनाव के 80% मानव जोखिम से बचा जा सकता है। गेटी इमेजेज/आईस्टॉकफोटो - Photo:

PRESS TRUST OF INDIA

ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि दुनिया भर में पहले से ही लागू नीतियों के परिणामस्वरूप 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की संभावना है।

नए शोध के अनुसार, यदि दुनिया 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाती है, तो हिमालय क्षेत्र के लगभग 90% हिस्से में एक वर्ष तक सूखा रहेगा।

जर्नल इंडिया में प्रकाशित निष्कर्षों से ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 जलवायु परिवर्तन , गर्मी के तनाव में मानव जोखिम में वृद्धि का 80% दर्शाता है
डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य का पालन करके बचा जा सकता है।

यूके में यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया (यूईए) के शोधकर्ताओं ने मात्रा निर्धारित की कि ग्लोबल वार्मिंग का स्तर बढ़ने के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर मानव और प्राकृतिक प्रणालियों के लिए जोखिम कैसे बढ़ता है।

भारत, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया और घाना पर केंद्रित आठ अध्ययनों के एक संग्रह में पाया गया कि वार्मिंग की प्रत्येक अतिरिक्त डिग्री के लिए सूखा, बाढ़, फसल की पैदावार में गिरावट और जैव विविधता और प्राकृतिक पूंजी के नुकसान में काफी वृद्धि होती है।

इसमें कहा गया है कि भारत में परागण 3-4 डिग्री पर आधा कम हो गया जबकि 1.5 डिग्री पर एक चौथाई कम हो गया।

टीम ने 3 डिग्री वार्मिंग के साथ कृषि भूमि के सूखे के जोखिम में बड़ी वृद्धि की भी सूचना दी: प्रत्येक देश में 50% से अधिक कृषि भूमि को 30 वर्षों में एक वर्ष से अधिक समय तक गंभीर सूखे के संपर्क में रहने का अनुमान लगाया गया था। अवधि।

तटीय देशों में समुद्र के स्तर में वृद्धि से जुड़े आर्थिक नुकसान में भी वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अगर वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा गया तो यह और धीरे-धीरे बढ़ेगी।

शोधकर्ताओं ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है क्योंकि दुनिया भर में पहले से ही लागू नीतियों के कारण तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

एक पेपर ने ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि के कारण पौधों और कशेरुकियों के लिए खतरों का पता लगाया, जबकि दूसरे ने छह देशों में से प्रत्येक के लिए एक नया प्राकृतिक 'पूंजी जोखिम रजिस्टर' विकसित किया, जिसमें भविष्य में मानव जनसंख्या परिवर्तनों से उत्पन्न जोखिमों में अनुमानित परिवर्तन भी शामिल थे।

संयोजन में उनके परिणामों से पता चला कि छह देशों में कई क्षेत्र पहले से ही 1.5 डिग्री सेल्सियस पर उच्च प्राकृतिक पूंजी जोखिम में हैं, जब उच्च मानव आबादी के प्रभावों को ध्यान में रखा जाता है।

यूईए के प्रोफेसर राचेल वॉरेन और अध्ययन के प्रमुख लेखक ने कहा, "इस संग्रह में प्रस्तुत परिणाम पेरिस समझौते की सीमाओं के अनुरूप जलवायु नीतियों के कार्यान्वयन की आवश्यकता की पुष्टि करते हैं, अगर व्यापक और बढ़ते जलवायु परिवर्तन के जोखिम से बचा जाना है।"

प्रोफेसर वॉरेन ने कहा, "वे इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज 2022 रिपोर्ट में पाए गए ग्लोबल वार्मिंग के साथ जलवायु परिवर्तन के खतरों के तेजी से बढ़ने की अतिरिक्त पुष्टि प्रदान करते हैं, जो पहचानती है कि ग्लोबल वार्मिंग में हर अतिरिक्त वृद्धि के साथ गंभीर परिणामों का खतरा कैसे बढ़ता है।"

शोधकर्ताओं ने कहा कि हालांकि ये अध्ययन केवल छह देशों के जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अन्य देशों को भी इसी तरह के मुद्दों का अनुभव होने का अनुमान है।